A Daily News Magazine
इंदौर
शनिवार, 30 मई, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 237, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले 'उदन्त मार्त्तण्ड' की द्विशताब्दी

विजयदत्त श्रीधर

लेखक 'समग्र भारतीय पत्रकारिता'-तीन भाग ग्रंथ के रचयिता एवं पत्रकारिता के लिए 'पद्मश्री' से विभूषित हैं।

हिन्दुस्तानियों के हित के हेत'...........यह हिन्दी पत्रकारिता की आदि प्रतिज्ञा है। इस संकल्प के साथ 30 मई, 1826 को हिन्दी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्त्तंड'प्रकाशित हुआ। इसके संपादक युगलकिशोर शुक्ल को हिन्दी पत्रकारिता का प्रथम संपादक होने का गौरव प्राप्त है।

जनवरी, 1931 तक यह माना जाता रहा कि हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत सन् 1845 में काशी से प्रकाशित होने वाले 'बनारस अखबार' से हुई। 'माडर्न रिव्यूस' के सहायक संपादक ब्रजेन्द्रनाथ बंद्योपाध्याय (बनर्जी) जब भारतीय भाषाओं की पत्रकार-कला का इतिहास लिख रहे थे, उनकी शोध दृष्टि में 'उदन्त मार्त्तंड' की फाइल आई। तब यह तथ्य सामने आया कि हिन्दी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्त्तंड' है।

'विशाल भारत' के सन् 1931 के फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई चार अंकों में ब्रजेन्द्रनाथ बनर्जी के शोध आलेख प्रकाशित हुए। तदनुसार 'उदन्त मार्त्तंड' का प्रवेशांक 30 मई, 1826 को प्रकाशित हुआ। 30×20 से.मी. फुलस्केप आकार के आठ पृष्ठों के इस समाचारपत्र के मुख पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर 'उदन्त मार्त्तंड' नाम होता था। इसके नीचे संस्कृत में लिखा जाता था- 'दिवाकान्ता कान्तिं बिनाध्वाान्तबमन्तंन नचाप्नोतति तद्वज्जवगत्यमज्ञ लोकः। समाचार सेवामृते ज्ञत्व माप्तुं नशक्नोाति तस्मात्कचरोमीति यत्नं।। 'इसका अर्थ है- सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता उसी तरह समाचार सेवा के बिना अज्ञ जन जानकार नहीं बन सकते। इसलिए मैं यह समाचारपत्र प्रकाशनरूपी प्रयत्न कर रहा हूँ। अर्थात् उदन्त मार्त्तंड का तात्पर्य है समाचार-सूर्य।

उदन्त मार्त्तंड के प्रत्येक अंक के अंतिम पृष्ठ। पर सबसे नीचे लिखा रहता था- 'युगल किशोरः कथयति धीरः सविनय मेतत सुकुलज वंशः। उदिते दिनकृति सती मार्त्तंडे तद्वद्विलसती लोक उदन्तेत। 'यह उदन्त मार्त्तंड कलकत्ते के कोल्हू टोला के अमड़ातला की गली के 37 अंक की हवेली के मार्त्तंड छापा में हर सतवारे मंगलवार को शाया होता है।'

प्रवेशांक में 'इस कागज के प्रकाशक का इश्तेहार' शीर्षक से समाचार पत्र का मंतव्य दिया गया है- यह उदन्त मार्त्तंड अब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ पारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है और सब लोग पराये सुख सुखी होते हैं जैसे पराये धन धनी होना ओ अपनी रहते पराई आँख देखना वैसे ही जिस गुण में जिसकी पैठ न हो उसको उसके रस का स्वाद मिलना कठिन ही है.........।'

उदन्त मार्त्तंड में प्रकाशित समाचारों के जितने भी उद्धरण देखने में आते हैं, उनसे पता चलता है कि हिन्दी पत्रकारिता के सर्वप्रथम संपादक को यह ज्ञान था कि पाठकों को किन घटनाओं, प्रवृत्तियों और समाचारों से अवगत कराना जरूरी है। सूचित करना पत्रकारिता का प्रथम कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है समाज को शिक्षित और प्रेरित करना। पत्रकारिता को लोकरंजन की दिशा में भी काम करना चाहिए, यह सात्विक अपेक्षा की जाती है।

उदन्त मार्त्तंड के संपादक की विचार-दृष्टि में भारत और भारतीयों के हित का महत्वतपूर्ण स्थान था। पाँच सितंबर, 1826 के अंक में 'विलायती कपड़ा'शीर्षक से विचारोत्तेजक टिप्पणी लिखी गई है-' इस देश में विलायती कपड़ों की आमदनी किस तरह से साल साल बढ़ती गई वह नीचे के लिखे ब्योरे के देखने से ही समझ पड़ेगा। '.........नौ साल का ब्यौरा देते हुए उदन्त मार्त्तंड के संपादक ने सवाल उठाया' जरा सोचिए कि कहाँ डेढ़ लाख रुपये साल का कपड़ा और कहाँ साठ करोड़ रुपये वार्षिक का! एक सौ पन्द्रह वर्ष में 4,00,00,00/- प्रति सैकड़ा की वृद्धि।

4 दिसंबर, 1827 को उदन्त मार्त्तंड का प्रकाशन बंद हो गया। इसका एक कारण यह था कि अन्यद भाषाओं के समाचारपत्रों को कंपनी सरकार से जैसी सहायता मिलती थी, वह उदन्त मार्त्तंड को नहीं मिली। डाक घर से समाचारपत्र के वितरण की सुविधा भी नहीं मिली। जिन हिन्दी भाषियों के हित के लिए युगलकिशोर शुक्ल ने समाचारपत्र प्रकाशित किया था, उन्होंने भी सहारा नहीं दिया। पत्र बंद होने की सूचना देने के लिए निम्नलिखित परचा जारी किया गया-

उदन्त मार्त्तंड की यात्रा
आज दिवस लौं उग चुक्यौ, मार्त्तंड उदन्त ।
अस्तावचल कौ जात है दिनकर दिन अब अन्त ।।
चल्यों सूर्य निज सदन युगल अपनौ कर खैंचों।
अबहू कैई निर्मोह मेट आगे को चौ चौ।।
गुण रवि को परकाश कहौ किम होय जड़नि मँह।
जहाँ जड़नि को मान ग्लानि ह्वै हैं वोहीं कँह।।

जब तें या कलकत्ता नगरी में उदन्त मार्त्तंड को प्रकाश भयौ तब लैं आज दिवस लौं काहू प्रकार तें ढांढस बाँध विद्या के बीच बैवे को हिन्दुस्तानियों के जड़ता के खेत को बहु विध जोत्यौ पहिले तो अैसी कठोर भूमि काहे कौ जुते। उदन्त मार्त्तंड ने हिन्दी। पत्रकारिता की ठोस नींव रखी। विगत दो सौ वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता का आशातीत विस्तार और विकास हुआ है। सारी दुनिया हिन्दी पत्रकारिता के दायरे में है। विषयों की विविधता है। अधनातुन प्रौद्योगिकी तक मुद्रण और संप्रेषण की प्रगति हुई है। हिन्दी भाषा और गद्य का उन्नियन हुआ है। यह तथ्य भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि जब टेलीविजन आया तब इसे मुद्रित माध्यम के लिए संकट कहा गया था। परंतु मुद्रित समाचार माध्यम आगे ही बढ़े हैं। वेब मीडिया, सोशल मीडिया जैसे अन्य संवाद माध्यम भी प्रिंट मीडिया के लिए चुनौती नहीं हैं। सबकी अपनी-अपनी भूमिका है।

हिन्दी पत्रकारिता ने स्थायी महत्व के दो बड़े काम किए। एक, देश और दुनिया के हालात और हलचलों में दिलचस्पी लेने वाला पाठक वर्ग तैयार किया। दूसरे, भाषा को नया रूप दिया और साफ-सुथरे, सुस्पष्ट और समर्थ गद्य की परंपरा का विकास किया।

हिन्दी पत्रकारिता के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि उसके मूर्धन्य संपादकों में हिन्दी तर भाषी मनीषियों का महत्वपूर्ण अवदान है। मराठी के माधवराव सप्रे, बाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे; बांग्ला के राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, अमृतलाल चक्रवर्ती, गुजराती के स्वानमी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, कन्नड के नारायण दत्त, तेलुगु के बालशैर रेड्डी प्रभृति मनीषियों की एक लंबी श्रृंखला है।

भारतेन्दु हरिशचन्द्र को हिन्दी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिन्दी के शब्द भण्डार को समृद्ध करने में बाबूराव विष्णु पराडकर के 'आज' (1920, काशी) के संपादकों की महती भूमिका है। हिन्दी गद्य के विन्यास और वर्तनी की एकरूपता के लिए सरस्वती संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कठिन साधना की। गणेशशंकर विद्यार्थी का 'प्रताप'और माखनलाल चतुर्वेदी का 'कर्मवीर'हिन्दी पत्रकारिता के गौरव हैं। हिन्दी में आध्यात्मिक पत्रिका का श्रेष्ठ उदाहरण है 'कल्याण'। अगस्त, 2026 में कल्याण के प्रकाशन के एक सौ साल पूरे हो रहे हैं। इसके संपादक थे भाईजी हनुमानप्रसाद पोद्दार।

बड़ा फैसला! अब नहीं चलेगी तारीख पर तारीख

● सुप्रीम आदेश, रिजर्व फैसलों को 3 महीनों में सुनाना अनिवार्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों में फैसले सुरक्षित रखने के बाद उन्हें सुनाने और ऑनलाइन अपलोड करने में हो रही अत्यधिक देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई फैसला रिजर्व करने के तीन महीने के अंदर सुनाया नहीं जाता, तो संबंधित हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल उसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अधिकतम दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। यदि इसके बाद भी पालन नहीं होता, तो केस दूसरी बेंच को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑपरेटिव पार्ट (मुख्य आदेश) की घोषणा के 15 दिनों के अंदर पूरा फैसला (कारण सहित) अपलोड करना अनिवार्य है। यदि 15 दिनों में कारण अपलोड नहीं किए जाते, तो

पक्षकार एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही 30 दिनों तक अपलोड नहीं होने पर पक्षकार केस वापस लेने या दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आवेदन दे सकेंगे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बहस पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व की तारीख हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए।

फैसला रिजर्व होने के बाद 3 महीने के अंदर सुनाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फैसला रिजर्व होने के बाद तीन महीने के अंदर उसे सुनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि खासतौर पर जमानत के मामलों में ऑर्डर रिजर्व होने के अगले दिन ही फैसला सुनाया जाना चाहिए। जमानत आदेश तुरंत जेल अधिकारियों को सूचित किए जाएंगे और अंडरट्रायल कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा कर दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट को इसकी अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजनी होगी। यह निर्देश झारखंड हाई कोर्ट में लंबित एक याचिका के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि उनकी आपराधिक अपीलों पर अंतिम बहस सुनने के बाद दो-तीन साल तक फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन सुनाया नहीं गया।

इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए सभी हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में पूछा गया कि कितने मामलों में महीनों या वर्षों से फैसले सुरक्षित पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को न्याय वितरण व्यवस्था की विश्वसनीयता से जोड़ते हुए कहा कि देरी से न्याय मिलने में बाधा आती है और जनता का न्यायपालिका पर भरोसा कम होता है। कोर्ट ने दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

महाराष्ट्र में जहरीली शराब से 15 की मौत

● सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए, अब तक 8 लोग हिरासत में

पुणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें हडपसर, फुगेवाड़ी, दापोडी और पिंपरी इलाके में हुई हैं। पुलिस और राज्य आबकारी विभाग ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक अवैध शराब कारोबारी भी शामिल है। जांच में सामने आया है कि शराब में मेथेनॉल हो सकता है। मामला सामने आने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित हाथ भट्टी की जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता तथा पूर्व महापौर योगेश बहल ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस का कहना है कि 5 लोगों की मौत अलग-अलग कारणों से हुई है। लेकिन मृतकों में कई लोगों को मौत से पहले चक्कर आया था, जिससे जहरीली शराब की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

सुप्रभात

लाख गम की आज फेरी
रात कितनी हो अंधेरी
पर सुबह के भोर से ही
सूर्य सा जलना चुना है
मैंने भी लिखना चुना है.....

ढेर दल दल हो दबाए
अपने हों या हों पराए
पर शिला को चीरकर भी
बीज सा उगना चुना है।
है शिकायत जन्म से भी
देर करती मृत्यु से भी
पर गरीबी के विरह से
न याचना करना चुना है।
बाप की औलाद खोटी
शब्दों के हिस्से न रोटी
व्यंग्य के आगोश रहकर
शब्दों से भिड़ना चुना है।
आज से कल भोर दुगनी
लाश उठती रोज कितनी
पर दया की रोटियों से
शौक से मरना चुना है
मैंने भी लिखना चुना है.....।

- शुभम शुक्ला अश्वत्थामा

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य पूर्ण

जल संरक्षण और संवर्धन के पुनीत कार्य में देश का अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री

● 10,644 करोड़ की स्वीकृत राशि से प्रदेश भर में संवर रहे हैं पारंपरिक जल स्रोत

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन का मुख्य आधार है और हमारी पारंपरिक जल संरचनाओं को संरक्षित और संवर्धित करना हमारा परम सामाजिक और पर्यावरणीय कर्तव्य है। इसी पावन उद्देश्य के साथ राज्य में शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' आज केवल एक शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सहयोग से एक पवित्र जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में जल संरक्षण और पुनर्जीवन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके अंतर्गत अब तक रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जल सहेजने के इस पुनीत कार्य में पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के तहत

राज्य में कुल 3,67,777 कार्यों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें से 2,00,844 महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार पूरा किया जा चुका है, जबकि 1,51,093 कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। इस विशाल अभियान को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 10,644.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से अब तक 6,330.81 करोड़ रुपये (लगभग 59.5%) की राशि का उपयोग किया गया है, जो विकास की वास्तविक गति को दर्शाती है।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई जल क्रांति

ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में जल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड 57,794 खेत तालाब और 91,838 डग वेल रिचार्ज (कुआं पुनर्भरण) संरचनाओं का निर्माण व जीर्णोद्धार किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक और नए जल स्रोतों को सहेजने के उद्देश्य से 29,906 जल संरक्षण एवं पुनर्भरण संरचनाओं तथा 126 भव्य 'अमृत सरोवरों' का कार्य शत्-प्रतिशत् पूरा किया जा चुका है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,152 विशेष सिंचाई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पुरानी जल संरचनाओं के पुनर्जीवन के लिए 2,721 मरम्मत एवं रखरखाव संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।

श्रीलंका में अटका 'मानसून', भारत पहुंचने में देरी

● अब 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगा, तूफानी हवाओं ने रोक लिया रास्ता ● 10 फीसदी कम बारिश का अनुमान, जून-जुलाई में भी हीटवेव चलेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते मानसून केरलम तट से 30-35 किमी दूर 5 दिन से अटका है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं हैं। केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है।

इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक ही मानसून आने का अनुमान जताया था। ताजा अनुमान के मुताबिक अब यह 7 दिन बाद केरल तट पर पहुंचेगा। यानी, पिछले अनुमान से मानसून करीब 10 दिन बाद देश में एंट्री करेगा।

इस साल बारिश भी 10 फीसदी तक कम होगी

मौसम विभाग ने बताया कि इस साल देश में औसतन 78 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान है। जो सामान्य से करीब 10 फीसदी कम है। 13 अप्रैल को 80 सेंटीमीटर बारिश का अनुमान लगाया गया था। 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर देश में औसत बारिश 87 सेंटीमीटर मानी जाती है। मौसम विभाग ने बताया कि जून में मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में सामान्य से भी कम बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश का अनुमान है।

इस साल अल-नीनो के चलते मानसून कमजोर पड़ेगा

मौसम विभाग ने कहा कि कमजोर मानसून के पीछे की वजह अल-नीनो है। जून में अल नीनो का असर दिख सकता है। जुलाई और अगस्त में भी कमजोर से मध्यम स्तर का अल नीनो बने रहने की संभावना है। अल नीनो के कारण समुद्र का पानी असमान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसके साथ हवा के पैटर्न में भी बदलाव आता है। इसके असर से दुनियाभर में बारिश का चक्र बिगड़ जाता है। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं मूसलाधार बारिश आती है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 30 मई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

मंदी के बीच भी भारत बना रहेगा मजबूत अर्थव्यवस्था

● राहत की खबर, 6.5 फीसदी रह सकती है विकास दर

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनियाभर के मुख्य अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि अगले एक साल में वैश्विक आर्थिक विकास धीमा होगा, लेकिन भारत एक ऐसे क्षेत्र के तौर पर सबसे अलग है जहां विकास की उम्मीदें सबसे ज्यादा हैं। वर्ल्ड इकोनमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने गुरुवार को एक सर्वे में यह बात कही। अपने ताजा चीफ इकोनमिस्ट्स आउटलुक में डब्ल्यूईएफ ने कहा कि सर्वे में शामिल लगभग दस में से नौ मुख्य अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि आने वाले साल में वैश्विक विकास धीमा होगा। हालांकि, सिर्फ 13 प्रतिशत लोगों को लगता है कि वैश्विक मंदी आ सकती है। सर्वे के मुताबिक, 94 प्रतिशत लोगों को उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से वैश्विक महंगाई बढ़ेगी, जिससे ऊर्जा और खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और सप्लाई चेन में रुकावट आएगी। मुख्य अर्थशास्त्रियों ने स्ट्रेट आफ होर्मुज के मौजूदा समय तक बंद रहने की स्थिति को पिछले साल की टैरिफ (शुल्क) से जुड़ी उथल-पुथल के मुकाबले कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। सर्वे में कहा गया है कि इस संकट का सबसे ज्यादा असर पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्रों पर पड़ने की उम्मीद है।

मणिपुर में तनाव के बीच सुरक्षाबलों का ऐक्शन

● बंधकों का पता लगाने में जुटीं एजेंसियां, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने गुरुवार को कहा कि सुरक्षा बल सशस्त्र समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का पता लगाने के लिए इलाके में खोजबीन अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांगपोकपी जिले के माखन नगा गांव के दौरे के दौरान बताया कि छह नगा लोगों के अपहरण में शामिल होने के संदेह में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और बंधकों का पता लगाने के लिए खोजबीन अभियान जारी है। कांगपोकपी और सेनापति जिलों में 13 मई को सशस्त्र समूहों द्वारा 38 से अधिक लोगों का अपहरण करके उन्हें बंधक बना लिया गया। इनमें से 31 लोगों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें 12 नगा महिलाएं और 16 कुकी शामिल हैं। हालांकि, छह नगा पुरुष अब भी बंधक बनाकर रखे गए हैं और उनके ठिकाने का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं, बुधवार को अखिल मणिपुर नुपी मारुप संगठन ने बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर इंफाल के इरावत भवन में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया।

हमें अपने 'युवाओं' को निराश नहीं करना चाहिए

● नीट यूजी केस में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, केन्द्र से मांगा हलफनामा

कहा-जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक असल समस्या हल नहीं होगी। हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो जाए तो यह वास्तव में बहुत ही दुखद होता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने को कहा, मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित की। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि प्रधानमंत्री स्वयं निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई खामी न रह जाए।

सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया जवाब

इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है। एनटीए ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कई ठोस कदम उठाए जा चुके हैं और भविष्य में भी मजबूत व्यवस्था लागू की जाएगी। एनटीए ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि हाई स्टेक परीक्षाओं में पेपर सेटर, मॉडरेटर, अनुवादक, प्रूफरीडर आदि को चुनने के लिए रैंडमाइजेशन और रोटेशन पॉलिसी को संस्थागत रूप दिया जा रहा है।

एनटीए ने बताया- एग्जाम को लेकर उठा रहे क्या स्टेप

एनटीए ने हलफनामे में बताया कि परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बैकग्राउंड को चेक करने में सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सुरक्षा जोखिम घटाने के लिए एनटीए अब अनुवाद कार्य के कम से कम 85 फीसदी हिस्से में एआई-बेस्ड टूल्स का उपयोग करेगी। इससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुरक्षित होगी। एनटीए ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि परीक्षा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देशभर के जाने-माने सरकारी संस्थानों में कम से कम 1,000 अत्याधुनिक सुरक्षित टेस्टिंग सेंटर बनाने की योजना है। इन केंद्रों पर क्लाउड-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई-एमएल, ब्लॉक चेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रोसेस की अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ निगरानी की जाएगी। तकनीकी मजबूती की बात करें तो केंद्रों पर एआई-इनेबल्ड रियल-टाइम सीसीटीवी मॉनिटरिंग लागू की जा रही है।

उज्जैन में मुख्यमंत्री ने किया भुजंगासन

● रिसोर्ट में ही रुके डॉ. मोहन यादव, भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में सुनाया महादेव का भजन

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत शुक्रवार को दूसरे दिन सीएम ने वर्ग में सुबह योग किया और फिर जाते जाते मंच से सभी को महादेव के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। राजाराम रिसॉर्ट में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का गुरुवार को शुभारंभ सीएम डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ था। दिन-भर वर्ग में सभी को भाजपा की विचार धारा के साथ चलने और नियमों का पालन करने की सिख दी।

रिसोर्ट में रात रुके, सुबह धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे- सीएम ने रात रिसोर्ट में ही गुजारी, शुक्रवार सुबह वर्ग के अंतिम दिन सीएम डॉ यादव ने रवाना होने से पहले प्रशिक्षण वर्ग में धोती कुर्ता पहनकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है और कार्यकर्ताओं के समक्ष मंच पर योगा कर मंच से एक उदाहरण पेश किया।

प्रशिक्षण वर्ग के समापन में 3 वर्ग हुए

मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा और प्रदेश प्रवक्ता राकेश पंड्या ने बताया कि शुक्रवार को प्रशिक्षण वर्ग के समापन में तीन वर्ग हुए जिसे प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, इंदौर जिले प्रभारी राजेश सोलंकी, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रशिक्षण वर्ग में सभी को सरकार की जान कल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कहा साथ ही पार्टी की विचारधार से सिखने और उसे भी जन-जन तक पहुंचाने अपने आप को दक्ष बनाने के साथ सरकार द्वारा शहर के विकास में चल रहे कार्यो की जानकारी भी रखने की सीख दी।

मप्र ने गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया : मुख्यमंत्री

● किसानों से अब तक 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया ● 24 हजार करोड़ रुपये का किसानों को किया जा चुका है भुगतान

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं उपार्जन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। प्रदेश में किसानों से अब तक रिकॉर्ड 1.4 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को 2585 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रति क्विंटल 40 रुपए बोनस का लाभ दिया है। किसानों को 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का भुगतान किया। अब तक किसानों को गेहूं उपार्जन की 24 हजार करोड़ राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन में आज वीडियो संदेश के माध्यम से ये जानकारी दी।

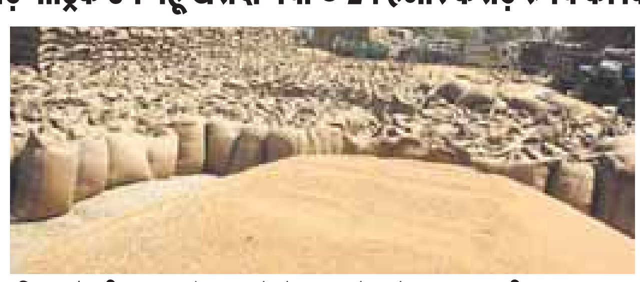

किसानों की संख्या के मामले में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूं खरीदने के लिए किसानों की संख्या के मामले में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं की पैदावार बढ़ी है। देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले राज्यों में पंजाब के बाद मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्यप्रदेश सर्वाधिक लंबे समय तक गेहूं खरीद की व्यवस्था लागू करने वाला एकमात्र राज्य है।

सरकारी खरीद के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं गोदामों तक पहुंच चुका है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों से पहले गेहूं खरीदा गया। यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की गई। छोटे किसानों से अब तक लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। इसके बाद बड़े किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिला। अब तक लगभग पौने 14 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कर लिया गया है। सरकारी खरीद के लिए पंजीयन कराने वाले सभी किसान भाई-बहनों का गेहूं गोदाम तक पहुंच चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस कठिन दौर में भी रिकॉर्ड गेहूं खरीदी की गई है। राज्य सरकार किसानों के लिए अनेक जन हितैषी निर्णय ले रही है। अन्नदाता भाई-बहनों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने यह पूरा वर्ष कृषक कल्याण को समर्पित किया है। प्रदेश का हर किसान समृद्ध और खुशहाल हो, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग से किसानों की आय में वृद्धि हो, यह हमारी प्रतिबद्धता है।

बिहार में भारी बारिश, 20 जिलों में दिन में अंधेरा

● बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, यूपी में तूफान का तांडव

लखनऊ (एजेंसी)। बिहार में शुक्रवार को आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना, खगड़िया,रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, छपरा समेत 20 जिलों में सुबह पहले अंधेरा छा गया फिर तेज बारिश हुई। राज्य में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। काले बादलों की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते देखे गए। मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उधर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में दिन में हीटवेव चलेगी, जबकि शाम को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। यूपी में गर्मी के बजाय बारिश-आंधी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और चंदौली में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। 100 किमी की रफ्तार से हवाएं चलीं। हमीरपुर में तूफान के चलते अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर गया। जिसमें 6 की मौत हो गई। लखनऊ में रेलवे स्टेशन का टिन शेड गिर गया। 2 लोग घायल हुए। राजस्थान में 12 जिलों में बारिश हो सकती है। देश में नौतपा के बीच 10 राज्यों में बारिश हो रही है।

घुसपैठियों ने बताया कैसे बांग्लादेश से भारत में घुसे

● कहा- दलालों को 20 हजार देकर 10 मिनट में पार किया बॉर्डर

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इसके चलते, हजारों बांग्लादेशी नागरिक अब सीमावर्ती इलाकों में जमा होने लगे हैं। डिटेंशन सेंटरों में बंद किए जाने के डर से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी इस समय पूरे बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों और ट्रांजिट टर्मिनलों पर इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे-जैसे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक सीमा पर जमा हो रहे हैं, ये प्रवासी अब इस बारे में खुलकर बात करने लगे हैं कि वे अवैध रूप से भारत में कैसे घुसे और उन्होंने पहचान पत्र कैसे हासिल किए।

● **टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क ने वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद की-** इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति ने खुलासा किया कि जब सुरक्षा बल इलाके में गश्त नहीं कर रहे होते हैं, तो सिर्फ दस मिनट में 20 हजार देकर भारत में घुसना संभव है। इसके अलावा, कुछ लोगों ने दावा किया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक नेटवर्क ने उन्हें पहचान पत्र बनवाने में मदद की। उन्होंने बताया कि वे भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा पाए और यहां तक कि वोट भी डाल पाए।

'साझा दुश्मन' से साथ निपटने की तैयारी

● भारत के बेहद करीब आ रहा है ऑस्ट्रेलिया ● हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक शांति का है प्लान

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही तेजी से भारत के बेहद करीब आ रहा है। गुरुवार को ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी संसद में भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भी भारत यात्रा पर आने वाले हैं। तीन दिन पहले ही ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री क्वाड की बैठक के लिए नई दिल्ली आए हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से कूटनीतिक तौर पर एक-दूसरे के करीब आना खास तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इस इलाके में चीन लगातार अपनी दखलंदाजी बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए क्षेत्र की दो महाशक्तियों की इस जुगलबंदी के खास मायने हैं।

संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध- ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस दूसरे ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्री संवाद में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चर्चा होगी। इससे पहले वे 23वें शांगरी-ला डायलॉग में शामिल हुए थे, जो कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक प्रमुख रक्षा मंच है। अपनी भारत यात्रा से पहले रिचर्ड मार्लेस ने बुधवार को कहा, बिगड़ते रणनीतिक माहौल में शांगरी-ला डायलॉग साझा चुनौतियों का सामना कर रहे पार्टनरों को एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराता है। **ऑस्ट्रेलियाई पीएम हुए हैं भारत के मुरीद-** गुरुवार को ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज अपनी संसद में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के साथ अपनी साझेदारी की अहमियत को प्रमुखता से अपने मुल्क के सामने रख चुके हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के वर्चस्व बढ़ने की चुनौती

भारत और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से साथ आने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, उसकी प्रमुख वजह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य दखलंदाजी है। क्वाड समूह का गठन भी इसी वजह से हुआ है, जिसकी विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग इसी हफ्ते अपने देश लौटे हैं। भारत या ऑस्ट्रेलिया में से किसी के लिए भी इस क्षेत्र में किसी एक विस्तारवादी देश (चीन) का वर्चस्व देख पाना संभव नहीं है। दोनों देशों के बीच बढ़ती जुगलबंदी का मतलब यही है कि यह क्षेत्र पहले की तरह वर्चस्व से मुक्त रहे।

ईरान से बनाई दूरी

होर्मुज में नहीं वसूलेंगे टोल

● ट्रंप की धमकी के बाद लाइन पर आया ओमान

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ओमान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर टोल लगाने की ईरान की योजना से किनारा कर लिया है। ओमान ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह ईरान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट यह जानकारी दी है। बेंसेट ने बताया कि ओमान के राजदूत से फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर टोल लगाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज पर टोल लगाने को लेकर ईरान को उड़ाने की धमकी दी थी। बेसेंट ने आगे कहा कि ओमान ने भरोसा दिलाया है कि वह ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।

होर्मुज खुलने के इंतजार में 2000 जहाज

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव की वजह से लगभग 2,000 जहाज इस समय खाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप के एक टॉप कैबिनेट मेंबर के इस खुलासे से पहली बार अंदाजा लगा है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर कितना बड़ा जाम लग चुका है। दुनिया के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बड़ा हिस्सा आम तौर पर इसी रास्ते से गुजरता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि करीब 2,000 जहाज खाड़ी से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।

भीषण गर्मी में प्यासा इंदौर, पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग, निगम पर आरोप

इंदौर। भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई देने लगा। शहर के अलग-अलग इलाकों में रहवासियों ने कांग्रेस पार्षदों के नेतृत्व में धरना देकर चक्का जाम किया। कई जगह खाली बर्तन लेकर पहुंचे लोगों ने नगर निगम और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालदा चौराहा और सुखलिया चौराहा पर हुए प्रदर्शनों की वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। तेज धूप में लोगों को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ा। बाद में निगम और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हो सकी। पालदा चौराहा पर वार्ड 75 और 64 के रहवासियों ने कांग्रेस पार्षद कुणाल सोनी के नेतृत्व में धरना दिया। इस दौरान पार्षद कुणाल सोलंकी पुलिस अधिकारियों के सामने भावुक हो गए। वे अधिकारियों के पैरों में गिर पड़े और दंडवत होकर रेंगते हुए पानी की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी नहीं है और जनता परेशान होकर मरने की स्थिति में पहुंच रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लंबे समय से पानी की आपूर्ति बाधित है और टैंकर व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। लोगों ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी शिकायतों के बाद भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

चौराहों पर धरना, चक्का जाम और नारेबाजी से थमी शहर की रफ्तार

निगम पर लापरवाही के आरोप

शहर में बढ़ते जल संकट को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि हर वर्ष अप्रैल के पहले पखवाड़े में जल संकट से निपटने की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मौसम विभाग पहले ही भीषण गर्मी की चेतावनी दे चुका था, इसके बावजूद मई के मध्य तक निगम प्रशासन गंभीर नहीं हुआ। जब तक अधिकारियों की नींद खुली, तब तक शहर के अधिकांश बोरिंग सूख चुके थे और हालात बिगड़ गए।

सुखलिया में भी फूटा गुस्सा

सुखलिया चौराहा पर पार्षद राजू भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और रहवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। चक्का जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। यहां रहवासियों ने आरोप लगाया कि पहले से चल रही जल वितरण व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। इससे मध्यमवर्गीय परिवारों और बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। लोगों का कहना था कि वे रोज पानी खरीदने में सक्षम नहीं हैं।

पानी को लेकर बढ़ रहा आक्रोश

पिछले करीब पंद्रह दिनों से शहर में पानी की समस्या को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने भी जल वितरण व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। विधायक महेंद्र हार्डिया ने नगर निगम पर असमान जल वितरण का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी थी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे महापौर के घर के बाहर धरना देंगे। वहीं एक दिन पहले वार्ड 26 के रहवासी भाजपा पार्षद लाल बहादुर वर्मा के साथ विधायक रमेश मेंदोला के घर पहुंचे थे और 'पानी दो' के नारे लगाए थे।

पानी वितरण रोकने का भी आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जल संकट के दौरान पार्टी के कुछ नेता अपने खर्च पर टैंकरों से पानी बंटवा रहे थे, लेकिन नगर निगम ने अब उन टैंकरों को पानी देना बंद कर दिया है। इससे संकट और गहरा गया है। प्रदर्शन के बाद निगम अधिकारियों ने नर्मदा लाइन, टैंकर व्यवस्था और जल आपूर्ति सुधारने का भरोसा दिया है। हालांकि रहवासियों का कहना है कि जब तक नियमित पानी नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इंदौर से नेपाल जाएगी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन

इंदौर। भारतीय रेलवे अब यात्रियों को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल की खूबसूरत वादियों और धार्मिक स्थलों तक भी खास टूरिस्ट ट्रेन के जरिए ले जाने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने पहली बार नेपाल के लिए 'भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन' लॉन्च की है। इस खास यात्रा का नाम 'पशुपतिनाथ नेपाल दर्शन यात्रा' रखा गया है, जो 12 जून से इंदौर से शुरू होगी। यह 10 दिनों की धार्मिक और पर्यटन यात्रा होगी, जिसमें यात्रियों को नेपाल के कई प्रसिद्ध शहरों और मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को एक ही पैकेज में धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सुंदरता और आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है। खास बात यह है कि यात्रियों को अलग से होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा पैकेज सभी सुविधाओं से युक्त रखा गया है। इस विशेष भारत गौरव ट्रेन के जरिए यात्रियों को नेपाल के कई लोकप्रिय पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।

अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन की कार्रवाई

इंदौर। अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन लगातार सतर्कता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज शहर के मध्य स्थित महाराजा कॉम्प्लेक्स में बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान एक अवैध रूप से कब्जाई गई दुकान में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए गैस से भरे हुए 25 गैस सिलेंडर जब्त किए। बताया गया कि सिलेंडरों का संग्रहण सुरक्षा मानकों के विपरीत किया जा रहा था, जिससे आगजनी जैसी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

चाइनीज की दुकान में आग लगी

इंदौर। परदेशीपुरा इलाके में गुरुवार शाम एक चाइनीज की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और दूर तक धुआं दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक, घटना नंदा नगर की गली नंबर 1 स्थित मजदूर चौक के पास की है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक लपटें पास की दो छोटी दुकानों तक पहुंच गईं। बाद में दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शर्मा चाट दुकान के धीरज शर्मा ने बताया कि आग पास में स्थित बोर्ड बनाने वाली दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आग की चपेट में आने से नजदीक का मेडिकल स्टोर और उनकी दुकान भी पूरी तरह जल गई। पार्षद मुन्नालाल यादव ने निगम के टैंकर भेजकर आग बुझाने में मदद की। बताया जा रहा है कि दमकलकर्मी मोटर चालू करने का पार्ट साथ लाना भूल गए थे। इसके बाद दूसरा पार्ट मंगवाकर टैंकर की मोटर चालू की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण किया

इंदौर। मुख्यमंत्री के निर्देशन में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में तालाबों के गहरीकरण तथा पर्याप्त जल पहुंच सुनिश्चित करने हेतु चैनल सफाई एवं जल संरक्षण के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा एवं आयुक्त नगर निगम क्षितिज सिंघल द्वारा विभिन्न स्थलों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा बिलावली तालाब में गहरीकरण कार्य, मोरोद-माचला चैनल सफाई कार्य, राऊ-बिलावली चैनल सफाई एवं पिचिंग कार्य तथा रालामंडल-बिलावली चैनल सफाई कार्य का जायजा लिया गया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि चैनलों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो तथा जहां अतिक्रमण पाया जाए वहां त्वरित रिमूवल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही तालाबों के गहरीकरण एवं जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

विकास की कीमत, पेड़ों की बलि, सड़क निर्माण में पुराने पेड़ काटे

मूसाखेड़ी-मयूर नगर में पेड़ों की कटाई पर लोगों में आक्रोश

इंदौर। शहर में विकास कार्यों के नाम पर हरियाली खत्म होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। मूसाखेड़ी और मयूर नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान वर्षों पुराने विशाल पीपल के पेड़ों की कटाई किए जाने से स्थानीय रहवासियों और पर्यावरण प्रेमियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रहे शहर में पेड़ों को बचाने के बजाय उन्हें काटा जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि नगर निगम चाहे तो बड़े पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर सकता था, लेकिन गंभीर प्रयास किए बिना ही पेड़ों की कटाई कर दी गई। क्षेत्रवासियों ने इसे हरियाली की हत्या बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।

पेड़ नहीं काटते, ट्रांसप्लांट करते

इधर, नगर निगम के जनकार्य प्रभारी राजेंद्र राठौर ने कहा कि निगम की नीति पेड़ों को बचाने की है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों में बाधा बनने वाले पेड़ों को नियमानुसार ट्रांसप्लांट किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पेड़ काटता है तो निगम आर्थिक दंड लगाकर कार्रवाई भी करता है। उन्होंने कहा कि पेड़ हटाने के लिए ऑनलाइन अनुमति प्रक्रिया अनिवार्य है।

छात्रा ने प्रेमी संग होटल जाने पर रची अपहरण, सामूहिक रेप की कहानी

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार

इंदौर। शिप्रा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी निकली। पुलिस की गहन तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि 16 वर्षीय छात्रा अपनी सौतेली मां के व्यवहार से बेहद परेशान थी। वह अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी, लेकिन रात में घर लौटने पर होने वाली डांट और डर के कारण उसने खुद के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की यह खौफनाक कहानी गढ़ दी। मूसाखेड़ी क्षेत्र की रहने वाली यह छात्रा बंगाली कॉलोनी में कोचिंग पढ़ने जाती है। बुधवार की देर रात परिजन उसे लेकर शिप्रा थाने पहुंचे थे, जहां उसने आरोप लगाया था कि कोचिंग से घर लौटते समय सिल्वर कलर की कार में आए तीन युवकों ने आंखों पर पट्टी बांधकर उसका अपहरण किया और सुनसान जगह ले जाकर

उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले को बेहद गंभीर जानकर इंदौर पुलिस तुरंत हरकत में आई। गुरुवार को जब पुलिस ने रास्ते के सीसीटीवी कैमरों की कड़ाई से जांच की, तो पूरी हकीकत सामने आ गई। फुटेज में छात्रा अंश नाम के एक युवक के साथ स्वेच्छा से जाती हुई दिखाई दी। इस सुराग के मिलते ही महिला पुलिस अधिकारियों ने जब छात्रा से दोबारा सहजता से पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया।

छात्रा ने स्वीकार किया कि वह अंश के साथ विजयनगर क्षेत्र के एक होटल में गई थी, जहां दोनों ने काफी समय बिताया। वहां से निकलने के बाद दोनों अपनी-अपनी गाड़ियों से शिप्रा पहुंचे थे। देर रात होने के कारण घर पर सौतेली मां के गुस्से से बचने के लिए उसने यह झूठा नाटक रचा था। गुरुवार को न्यायालय में छात्रा के बयान दर्ज कराए जाने के बाद इस पूरे मामले का पूरी तरह पर्दाफाश हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रेमी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

हाई कोर्ट ने कहा, मतांतरण कर विवाह पर 24 घंटे सुरक्षा नहीं!

केवल आशंका के आधार पर नहीं दिए जा सकते आदेश

इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक दंपती को चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल सामान्य आशंकाओं, संदिग्ध गतिविधियों या कुछ घटनाओं के आधार पर लगातार निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। अपने फैसले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि असाधारण सुरक्षा मांगने वाले मामलों में ठोस और स्पष्ट खतरे के प्रमाण जरूरी होते हैं। मामला रतलाम निवासी दंपती से जुड़ा है, जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दावा किया था कि कुछ लोग उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। याचिका में कहा गया कि कई बार उनकी कार रोकने की कोशिश की गई, घर के आसपास संदिग्ध वाहन घूमते दिखाई दिए और उन्हें लगातार डर का माहौल महसूस हो रहा है। दंपती ने विशेष रूप से रात के समय अतिरिक्त सुरक्षा और चौबीस घंटे पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

अदालत सुरक्षा नहीं कर सकती - मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जय कुमार पिल्लई ने कहा कि केवल आशंका या संदिग्ध वाहनों की मौजूदगी को आधार बनाकर निजी हथियारबंद सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अदालत ने माना कि ऐसे मामलों में सामान्य पुलिस गश्त और आवश्यक जांच पर्याप्त होती है। अदालत सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका निभाते हुए हर मामले में विशेष सुरक्षा बल तैनात करने के आदेश नहीं दे सकती। याचिका में दंपती ने बताया कि महिला पहले इस्लाम धर्म मानती थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाया और वर्ष 2019 में दिल्ली के एक आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया। उनका कहना था कि धर्म परिवर्तन और विवाह की जानकारी परिवार को मिलने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिलने लगीं। इसी कारण उन्होंने वर्ष 2022 में भी हाई कोर्ट का रुख किया था। उस समय अदालत ने रतलाम पुलिस अधीक्षक को कानून के अनुसार सुरक्षा संबंधी आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए थे।

सुरक्षाकर्मी को हटाया - दंपती ने अपनी नई याचिका में यह भी आरोप लगाया कि 13 अप्रैल को उनकी सुरक्षा में तैनात हथियारबंद गार्ड को बिना स्पष्ट कारण हटा दिया गया। उसकी जगह एक होमगार्ड जवान को तैनात किया गया, जिसके पास न हथियार था और न ही संपर्क के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया था। वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि दंपती द्वारा लगाए गए आरोप पर्याप्त प्रमाणों से समर्थित नहीं हैं। सरकार का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज करते हुए विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

छेड़छाड़ की शिकायत करने पर परिवार पर हमला, सबको पीटा

पुलिस ने सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की

इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अश्लील मैसेज भेजने के विवाद के बाद एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने मामले को सामान्य मारपीट मानकर हल्की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। एरोड्रम पुलिस ने अंबिकापुरी निवासी एक महिला की शिकायत पर विश्व प्रताप सिंह ठाकुर, शुभ, दादा, तनिष और अन्य साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। गुरुवार को पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत लेकर डीसीपी से मुलाकात की। महिला के अनुसार 23 मई की शाम उनकी नाबालिग बेटी के मोबाइल पर विश्व प्रताप की ओर से अश्लील संदेश भेजे गए थे। इस संबंध में बात करने के लिए महिला अपने पति और बेटे के साथ आरोपी के घर पहुंची थीं। घटना का दृश्य आसपास लगे कैमरों में भी रिकॉर्ड हुआ है। मारपीट से जुड़ा दृश्य सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बात बढ़ी तो मारपीट की

पीड़ित परिवार का आरोप है कि बातचीत के दौरान विश्व प्रताप गुस्से में आ गया और धमकी देने लगा। इसी बीच उसके पिता भी मौके पर पहुंच गए। परिवार का कहना है कि बिना पूरी बात सुने आरोपियों ने हमला शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक आरोपियों ने लकड़ी, स्टंप और लात-घूंसों से हमला किया। बीच-बचाव करने पहुंची महिला और उनकी नाबालिग बेटी के साथ भी मारपीट की गई। महिला ने बताया कि हमले के दौरान वह बेहोश होकर गिर गई थीं।

सूचना देने के बाद पहुंची पुलिस- परिवार का कहना है कि घटना के बाद भी आरोपी लगातार धमकियां देते रहे। हालात बिगड़ने पर महिला के पति ने 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी का परिवार इलाके में प्रभावशाली माना जाता है और आरोपी के पिता सरकारी नौकरी में हैं। इसी दबाव के कारण पुलिस ने गंभीर आरोपों के बावजूद सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया। महिला ने यह भी कहा कि पुलिस की ओर से उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा और मदद नहीं मिल पा रही है।

शंकरगंज में उजड़े आशियाने, चारों तरफ मलबा, दो बुजुर्गों की मौत से पसरा मातम

तोड़फोड़ से बिखरे परिवार, लोगों ने कहा, घर टूटने का सदमा सहन नहीं

इंदौर। जिंसी क्षेत्र से लगे शंकरगंज में नगर निगम की कार्रवाई के बाद पूरा इलाका गहरे दुख और आक्रोश में डूबा हुआ है। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हुई तोड़फोड़ के बाद यहां दो बुजुर्गों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और परिजनों का कहना है कि दोनों अपने पुश्तैनी घरों को टूटते नहीं देख सके और सदमे ने उनकी जान ले ली। गुरुवार को निगम की जेसीबी शंकरगंज पहुंची थी। इससे पहले रहवासियों को नोटिस देकर 5 मई तक का समय दिया गया था, जिसे बाद में 3 दिन और बढ़ाया गया। कई परिवारों ने अपने स्तर पर बाधक हिस्से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन कार्रवाई के दौरान कई मकान पूरी तरह ढह गए। 9 शंकरगंज निवासी 80 वर्षीय देवीबाई यादव की मौत के बाद परिवार शोक में है। उनके भतीजे सतीश यादव बताते हैं कि बड़ी मां शादी होकर इसी 15 बाय 61 के मकान में आई थीं। तीन मंजिला कच्चे घर में उन्होंने छह बेटों, एक बेटी, दो भतीजों और पूरे संयुक्त परिवार को संभालते हुए जीवन बिताया था। शंकरगंज की गलियों में अब मलबा, टूटे दरवाजे और उजड़े घर ही दिखाई दे रहे हैं। जिन आंगनों में वर्षों तक संयुक्त परिवारों की रौनक थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है।

घर टूटता देख व्यथित हुई

परिवार के मुताबिक देवीबाई पहले से थोड़ी अस्वस्थ थीं, लेकिन जब घर तोड़ने की नौबत आई तो वे बेहद व्यथित हो गईं। परिवार ने खुद छज्जा हटाने की कोशिश की थी। पड़ोसी आकाश

तिवारी ने भी अपना मकान इसलिए नहीं तोड़ा ताकि यादव परिवार के कच्चे मकान को नुकसान न पहुंचे, लेकिन निगम की जेसीबी चलते ही बाधक हिस्से के साथ पूरा मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने के बाद परिवार के सभी सदस्य शहर के अलग-अलग इलाकों में किराए के घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। परिवार का कहना है कि शिवाजी मार्केट स्थित उनकी दो दुकानों पर भी अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

घर की हालत देखकर चल बसे

इसी बस्ती में रहने वाले 72 वर्षीय ओमप्रकाश जोशी की भी कार्रवाई के बाद मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उन्होंने खुद अपने मकान का बाधक हिस्सा हटा दिया था। बच्चों ने उनके लिए महालक्ष्मी नगर में दूसरा मकान भी बना लिया था, लेकिन वे पुश्तैनी घर छोड़ना नहीं चाहते थे। कार्रवाई के दिन बच्चे उन्हें शंकरगंज नहीं आने दे रहे थे, लेकिन शाम को वे यहां पहुंचे। घर की हालत देखकर वे पूरी रात खामोश रहे और रोते रहे। अगले दिन उनका निधन हो गया। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।

200 साल पुरानी बस्ती

शंकरगंज के रहवासी और रूपांकन वाचनालय से जुड़े अशोक दुबे का कहना है कि यह करीब 200 साल पुरानी बस्ती है। उनका कहना है कि होलकर काल में यहां किला बनने के बाद सैनिकों और परिवारों के रहने के लिए यह इलाका बसाया गया था। अधिकांश मकानों की रजिस्ट्री है और लोग वर्षों से कर भी जमा कर रहे हैं। दुबे ने बताया कि मास्टर प्लान में यह व्यवस्था है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सीधे मकान नहीं तोड़े जाएंगे। यदि कोई नया निर्माण करना चाहे तो उसे निर्धारित सीमा छोड़ने के निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तोड़फोड़ की चपेट में रूपांकन वाचनालय भी आया है, जहां आसपास के गांवों से आने वाले विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वाचनालय का बड़ा हिस्सा भी ढहा दिया गया।

संपादकीय

बशीर बद्र : अजीम शायर का जाना

उर्दू के नामचीन और हर दिल अजीज शायर बशीर बद्र का इस फानी दुनिया से जाना न केवल उर्दू शायरी की अपूरणीय क्षति है, बल्कि इंसानियत के हक में खड़ी एक लाजवाब आवाज का उठ जाना भी है। बशीर साहब के कई शेर आज आम लोगों की जुबान पर है। वो केवल किताबी शायर नहीं थे, जनता के जज्बात के शायर भी थे। बशीर साहब का इंतकाल भले भोपाल में लंबी बीमारी के बाद हुआ हो, लेकिन उनकी पैदाइश 15 फरवरी 1935 को कानपुर में हुई थी। उनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर था। बशीर बद्र का पैतृक गांव अयोध्या (फ़ैज़ाबाद) जिले का बक़िया बताया जाता है। पिता की नौकरी के सिलसिले में कई शहरों में उनका रहना हुआ। बाद में वो मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। इंसानियत और भाईचारे के इस शायर के साथ विडंबना यह रही कि दंगाइयों ने 1987 में उनका ही घर जला दिया। उसके बाद से बशीर साहब का मेरठ पर से भरोसा उठ गया और वो स्थायी रूप से भोपाल आ बसे और उनका निधन भी यहीं हुआ। जिंदगी की जद्दोजहद और विसंगतियों को बेहद खूबसूरती और सलीके से अपनी गजलों में कह देना बशीर बद्र साहब की ख़ासियत रही है। उन्होंने उर्दू गजल को एक नया लहजा दिया। अपने श्रोता और पाठकों के दिलों में अपनी ख़ास जगह बनाई। मेरठ के दंगों के समय बद्र साहब ने यह लाजवाब शेर लिखा था- लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। बशीर साहब ने जिंदगी में अनेक झंझावात झेले। लेकिन चाहने वालों की मोहब्बत ने उनका सारा-गिला शिकवा दूर कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि बशीर साहब ने संत कबीर के 'बुरा जो देखन मैं चला' की तर्ज पर अपने भीतर झांकना सीख लिया था। बशीर साहब का एक शेर तो इतना मकबूल हो चुका है कि कई बार बसों ट्रकों पर लिखा मिल जाता है। ये 'उजाले यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।' उनके जाने कितने शेर हैं जो कल्ट बन चुके हैं। मसलन 'दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा न हों। या फिर 'कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो। बशीर बद्र की शायरी की एक और खूबी सरल और सहज भाषा है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू का भी वो रूप चुना, जो आम श्रोता की समझ आता था, उसके दिल की गहराइयों को छूता था। शब्दों के आडम्बर की जगह आसान मगर दिलकश लफ्जों का खूबसूरती से इस्तेमाल और बात कहने का अलग अंदाज, नई उपमाएं और रूपक बशीर साहब की खूबी थी, जो उन्होंने अपने समय के तमाम दूसरे शायरों को अलग साबित करती थी। यही कारण है कि बशीर साहब जितने उर्दू में पढ़े-सुने जाते थे, उससे कहीं ज्यादा हिंदी में सुने और सराहे जाते रहे हैं। जनता के शायर के तौर पर उनकी तुलना उन्हीं के समकालीन शायर दुष्यंत कुमार से की जा सकती है। हालांकि दुष्यंत हिंदी के कवि थे और उन्हें उर्दू में वैसी तवज्जो नहीं मिली, जैसी कि मिलनी चाहिए थी। बशीर बद्र साहब जिंदगी के आखिरी सोलह साल मौत से लड़ते रहे। उन्हें डिमेंशिया की बीमारी थी। उन्होंने 2010 में आखिरी बार किसी मुशायरे में हिस्सेदारी की थी। उसके बाद उनकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरी। लेकिन अपने पीछे लाजवाब शायरी का जो खजाना वो छोड़ गए हैं, आने वाली नस्लों के लिए भी विरासत है। 'सुबह सवेरे' की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि।

मतदाता ही हमारे लोकतंत्र की अंतिम आशा

नजरिया

कुमार प्रशांत
लेखक 'गांधी शांति प्रतिष्ठान' के अध्यक्ष हैं।

पांच राज्यों के चुनावी नतीजों ने पचासों सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन - देश की मतदाता सूची बनाना, उसे जांचते व सुधारते रहना 'चुनाव आयोग' का - एकमात्र चुनाव आयोग का - दायित्व है। एक से दूसरे चुनाव के बीच इस आयोग के पास संविधान द्वारा दिया दूसरा कोई काम नहीं होता, सिवाय इसके कि वह मतदाता सूची को पाक-साफ करता रहे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अयोग्य भी है और अपराधी भी। अगर वह ऐसा कहता है कि इस या उस सरकार ने घुसपैठिए घुसाकर, मतदाता सूची दूषित कर दी है, तो उसे देश को बताना ही पड़ेगा कि उसने कब, कहां, किससे इसकी शिकायत की?

संविधान के निर्माता इसके प्रति बेहद सावधान थे कि लोकतांत्रिक चेतना व संवैधानिक प्रावधान हमारे लिखे शब्दों से एक हद तक ही सुरक्षित व संरक्षित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान में ही ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था खड़ी की जो लोकतंत्र की जड़ें सींचें, संरक्षण के लिए बाड़ें खड़ी करें। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही नहीं, दूसरी भी कई संरचनाएं बनाई गईं जिनका काम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूत, स्वस्थ व गतिशील बनाना है।

संविधान निर्माताओं के मन में शंका थी कि सत्तालोलुप सरकारें व कायर-चापलूस नौकरशाही के कारण यह खतरा कभी भी उभर सकता है जब लोकतंत्र का ढांचा बना रहे, लेकिन उसकी आत्मा का लोप हो जाए। ऐसा जब भी होगा, लोकतंत्र एक बाजारू व्यवस्था भर रह जाएगा जिससे सभी निहित स्वार्थ फुटबॉल खेलेंगे। ऐसी शंका में से जन्म हुआ न्यायपालिका की संवैधानिक अवधारणा का! संविधान ने न्याय-व्यवस्था के भीतर ही एक ऐसी न्यायपालिका की संरचना की जो सबसे पहले व सबसे अंत तक संविधान के शब्दों की संरक्षक रहेगी तथा संविधान की आत्मा को प्रखरता से स्थापित करेगी।

हमारे संविधान ने एकमात्र न्यायपालिका के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जिसे संविधान के अलावा दूसरे किसी का बोझ नहीं ढोना है; संविधान के अलावा दूसरे किसी की नहीं सुननी है; संविधान के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहना है; संविधान के अलावा दूसरा कुछ नहीं देखना है। उसने एकमात्र इसी संस्थान की कुंडली में लिख दिया कि इसे हमेशा विपक्ष में ही रहना है - राजनीतिक दलों व संगठनों वाला विपक्ष नहीं, संवैधानिक विपक्ष! न्यायपालिका के हाथ में संविधान का गांडीव देकर उसने कह दिया : तुम्हारी नजर हमेशा उस मछली की आंख पर होनी चाहिए जो संविधान की मर्यादा से बाहर जा रही हो। संविधान ने ऐसी सजग व संवेदनशील न्यायपालिका बनाई और फिर खुद को भी उसी के हाथों में सौंप दिया - 'मेरा संरक्षण और मेरा संवर्धन भी तुम्हारा दायित्व है। यह तुम्हारे होने की सार्थकता भी है और तुम्हारे होने की कसौटी भी।'

क्या हमारी न्यायपालिका को इस दायित्व का अहसास है? क्या हमारी न्यायपालिका लोकतंत्र के कठघरे में खड़ी होकर, शपथपूर्वक कह सकती है कि लोकतंत्र के संरक्षण व संवर्धन का दायित्व उसने सौ टंच निभाया है? सौ टंच इसलिए कि संविधान का आधा-अधूरा निर्वाह अर्थहीन अवधारणा है। संविधान या तो है, या नहीं है ! अगर संविधान है तो श्रीमान सूर्यकांत हमें बताएं कि यह कैसे संभव हुआ कि बंगाल में 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए? क्या 'चुनाव आयोग' को चुनाव के ठीक पहले ऐसा करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय के जिन गलियारों से गुज़रकर वे रोज़ अपने चैंबर में पहुंचते हैं, उन गलियारों में 'सर' (एसआईआर, 'विशेष गहन पुनरीक्षण') की गूंज लंबे वक्त से गूंजती रही है।

बिहार चुनाव के वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा दिखाया कि वह मतदाता सूची के मामले में आयोग की मनमानी चलने नहीं देगा, लेकिन बिहार में चुनाव लूट लिया गया। संविधान को धोखा देकर, संवैधानिक नैतिकता को रौंदकर एक अनैतिक गठबंधन को उसी तरह सरकार बनाने का मौका दिया गया जिस तरह महाराष्ट्र में दिया गया था। इससे लोकतंत्र को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, न्यायपालिका अनैतिकता के दायरे में आ गई।

जब वोट चोरी का साक्ष्य सामने आया, एकाधिक बार, एकाधिक निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में, तब न्यायपालिका ने क्या किया? न्यायाधीशों की तरह संविधान के पंडित न भी हों, तो भी हम ऐसे मामले में पहला आदेश यही जारी करते कि वोट चोरी के साक्ष्य की जांच के लिए न्यायालय की समिति गठित की जा रही है और जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, 'चुनाव आयोग' दूसरा कोई भी चुनाव संचालित नहीं कर सकेगा। तत्काल न्यायिक जांच का आदेश हुआ होता तो इस पतनशील व्यवस्था पर लगाम लग जाती।

बंगाल के बारे में सामान्य विवेक व लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति एक ही आदेश देता कि बंगाल में चुनाव घोषित समय से ही होंगे, लेकिन 'चुनाव आयोग' के निकम्मेपन के कारण, उसे विधानसभा के पिछले चुनाव की मतदाता सूची का ही पालन करना होगा। चुनाव से काफी पहले मतदाता सूची जांच-परख ली जाए, ताकि उसे लेकर मतदाता के मन में कोई आशंका न रह जाए, यह दायित्व 'चुनाव आयोग' का है। अगर वह अपने दायित्व के निर्वाह में विफल रहा है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, न कि संवैधानिक प्रक्रिया को। संविधान ने आयोग के वर्चस्व की ऐसी व्यवस्था कर भी रखी है और अब तक ऐसा ही होता भी आया है।

बिहार से चलकर बंगाल पहुंची 'चुनाव आयोग' और सरकार की जुगलबंदी की अनदेखी करेंगे तो भ्रमित होंगे व गलत नतीजों पर भी पहुंचेंगे। क्या न्यायपालिका ने बंगाल में यह नहीं देखा कि इस बार हिंसा का आयोजन दिल्ली से हुआ है; उसकी कमान 'चुनाव आयोग' ने संभाल रखी है। भद्रजन जिसे 'हेटस्पीच' कहते हैं और संविधान जिसे लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार मानता है, वैसा कारनामा प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का हर ऐरा-गैरा, नत्थू-खैरा करने में लगा रहा। लाखों मतदाताओं के नाम रद्द करने की धौंस से नागरिकों में लाचारी व अपमान का माहौल बना, मनमाने प्रशासनिक फेरबदल ने स्थानीय स्वायत्तता को ध्वस्त कर दिया, सुरक्षा-बलों की छावनी जिस तरह बंगाल में उतारी गई, उसने एक तरफ़ बंगाली मतदाताओं को भयाक्रांत किया तो दूसरे बंगालियों को हमलावर भी बना दिया।

सुप्रीमकोर्ट को इस बात का अहसास है क्या कि जब-जब उसे संविधान के संरक्षण में चीते की फुर्ती से आगे आना चाहिए था, तब-तब वह कायरता से घिरा बैठा मिला! भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में 'आपातकाल' एक विभाजक रेखा बनाता है। वहां से देखें कि नागरिक स्वतंत्रता का सवाल हो कि प्रेस पर सेंसरशिप का कि नक्सली बताकर, राज्य द्वारा अनगिनत लोगों की हत्या का, वोट चोरी का या मतदाता सूची में मनमानी दखलंदाजी का, ऐसा क्यों है कि संविधान की प्रतिष्ठा और राज्य के आतंक के बीच चुनाव का नाजुक क्षण जब भी आता है, हमारी न्यायपालिका को लकवा मार जाता है? बाबरी मस्जिद ध्वंस का सवाल हो कि 'चुनावी बांड' की वैधता का, न्यायपालिका अपेक्षित प्रखरता से सामने नहीं आ पाती है, तो क्यों? जवाब गांधी देते हैं : 'जिन्हें हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं वे सब निर्णायक क्षणों में सत्ता के साथ खड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि अंततः ये सब उसके ही उपकरण हैं।'

यह बात बार-बार कहने व न्यायपालिका द्वारा लगातार दोहराने की है कि हमारी नागरिकता व मतदाता की हैसियत भारतीय राज्य की कृपा से नहीं है। यह हमें हमारे संविधान से स्वतः ही मिलती है। संविधान ने किसी 'चुनाव आयोग' को, किसी सरकार को, लोकसभा या राज्यसभा के किसी अध्यक्ष को या कि किसी राज्यपाल को अपवादस्वरूप भी ऐसी मनमानी शक्ति नहीं दी है कि वह नागरिक को उसकी नागरिकता से या मतदाता को उसके मतदान के अधिकार से वंचित कर दे। न्यायपालिका का इतना बड़ा सफेद हाथी हमने इसलिए पाल रखा है ताकि गाढ़े वक्त में वह लोक के साथ खड़ा हो, न कि तंत्र की तरफदारी करे, लेकिन लगता है वह सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनकर रह गई है। निर्भीक तटस्थता से लैस मतदाता ही हमारे लोकतंत्र की अंतिम आशा है जो न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका व मीडिया को अंकुश में रखेगा। (सप्रेस)

वन सुरक्षा समितियों में हेराफेरी, रोग की जड़ पहचानें

मुद्दा

श्याम बोहरे
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

गुरुवार 28 मई 2016 के सुबह सवेरे में 'वन सुरक्षा समितियों में करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा' समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है जिसमें वन सुरक्षा समितियों द्वारा किये गए भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह हांडी का एक चावल है और बीमारी को केवल पत्तों में देखने वाली है। इनका फौरी इलाज तो हो जायेगा, यदि शासन बीमारी मिटाना चाहे तो इलाज जड़ का करना होगा।

इस बीमारी को जानने के लिए वन सुरक्षा समितियों के उदगम से शुरुआत करते हैं। दरअसल यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रित व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश है। जैसा कि लोकतंत्र को जाना जाता है यह जनता का राज, जनता के द्वारा राज करना है। इसी को जमीन पर उतारने के लिए पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने 1977 के आसपास मिदनापुर जिले के आरावारी वन मण्डल में शोध के दौरान एक प्रयोग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन की पहल की जिसमें वनों की सुरक्षा, रख-रखाव और विकास के काम शासकीय अमले के साथ साथ जनता भी संयुक्त रुप से करे। 1990 में मध्य प्रदेश में इसकी पहल हरदा के तत्कालीन डी.एफ.ओ. ने की। फरवरी 1991में हरदा वन मण्डल के रहटगांव रेंज के बड़वानी गांव में पहली वन सुरक्षा समिति बनी। हरदा वन मण्डल के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए शासन ने 1991 में संकल्प जारी कर पूरे प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन लागू कर दिया। 1994 में विश्व बैंक के सहयोग से बड़े पैमाने पर वृहद प्रशिक्षण आयोजित हुए। हरदा वन मण्डल की सफलता को देखने के लिए देशभर से और विदेशो से लोग आये। औपचारिकतावश प्रशसा के लिए मजबूर अधिकारी अनौपचारिक चर्चा में इसे पानी पी-पी कर कोसते रहे। प्रत्यक्ष विरोध संभव न था इसलिए अनौपचारिक तरीके से जानकारी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को देकर विरोध के प्रयास भी हुए, जिसके फलस्वरुप विश्व बैंक का 7 साल का सहयोग 5 साल में वापस हो गया। वैसे भी विश्व बैंक का वित्तीय समर्थन स्थाई तो होता नहीं है। जब खतम न कर सके तो संयुक्त वन प्रबंधन दुधारु गाय बना ली गई इसलिए अवधारणा से विरोध होते हुए भी इसे जारी रखा। अपवादस्वरुप कुछ अधिकारी इसे निष्ठापूर्वक भी करते रहे। हमारी व्यवस्था जन और तंत्र में हर संभव दूरी बनाकर भी जनतंत्र का ढोल पीट-पीट कर शो-केस में सजाने में माहिर है। संयुक्त वन प्रबंधन इसकी सफल केस स्टडी हो सकती है।

बीमारी को जानने के लिए कुछ जांचों के नतीजे देखिए। जनभागीदारी के लिए वनों के पास के गांवों में वन सुरक्षा समितियां बनाई गईं जिनमें उस गांव के सभी वयस्क मतदाता सदस्य बनाये गए। दिन प्रति दिन के कार्य संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनी। सभी सदस्यों की भागीदारी की उपेक्षा करते हुए कार्यकारिणी समिति को ही वन सुरक्षा समिति मान लेने की प्रथा बन गई है। वन विभाग के संकल्प के अनुसार वन समिति, ग्राम सभा द्वारा

गठित की जाती है। ग्राम सभा की अनदेखी करते हुए वन विभाग के कर्मचारियों ने ही बिना किसी से सलाह किए 'जनभागीदारी से' समितियां बना दीं गईं। हमारी प्रशासनिक मशीनरी इतनी सक्षम है कि एक 'प्रतिभाशाली' अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केवल एक घंटे में प्रदेश के 52 हजार 600 गांवों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां बना दीं, जो काम ग्राम सभाओं को जन से संवाद और सलाह से करना था वह तंत्र के एक बंदे ने आनन फानन करके जनतंत्र को 'मजबूत' बनाया। इस कमाल पर तो जनतंत्र जिन्दाबाद कहना चाहिए।

एक प्रशिक्षण के दौरान हम वन विभाग के कर्मचारियों का स्थानीय समिति से संवाद कराने के लिए गांव गए। कुछ अंदाज था इसलिए गांव में पहुंचते ही मैंने रेंजर साहब से कहा मेरी डायरी रेस्ट हाउस में रह गई है ले आइये। रेंजर साहब की गैर हाजिरी में समिति के सदस्यों से संवाद शुरु किया तो समिति के अध्यक्ष को पता ही नहीं था कि वे अध्यक्ष हैं, न ही कार्यकारिणी के सदस्यों को। जब रेंजर साहब आए तो उन्होंने बताया कि ये अध्यक्ष हैं और ये सदस्य, रेंजर साहब की 'आज्ञा का पालन करते हुए' सभी लोगों ने कहा, जी साहब, जी साहब। यह रहा जनभागीदारी की जांच का एक नमूना।

सिवनी जिले के वरिष्ठतम वन अधिकारी से मेरी निकटता के कारण विभागीय कर्मचारी महत्व देते थे। एक दिन गांव में रुका और फारेस्ट गार्ड से कहा आपके यहां भोजन करेंगे। प्रसन्नता और अति उत्साह में उन्होंने श्रेष्ठतम व्यवस्था की। कुछ जानकारी लेने के लिए काफी समय तक उनके निवास पर रहा, हमारी बात होती रही, वे जानकारी देते रहे। वहां मैंने जन और तंत्र के सम्बंधों को देखकर जनतंत्र का जो रुप जाना वह मेरे अध्यापकीय ज्ञान में इजाफा है। एक सज्जन झाड़ू लगा रहे थे, दूसरे पानी भर रहे थे, तीसरे सब्जी काट रहे थे, चौथे चूल्हा जलाने में और पांचवें भोजन बनाने की अन्य तैयारियां कर रहे थे। तंत्र के सबसे जूनियर कर्मचारी जो समिति के सचिव की हैसियत से समिति के सहायक थे, जन के पांच सदस्यों से बतौर नौकर काम करा कर जनसेवक का दायित्व निभाते हुए जनतंत्र का नया माडल पेश कर रहे थे। वे पांचों सदस्य ग्राम वन सुरक्षा समिति की कार्यकारिणी के 'सम्मानीय' सदस्य थे।

जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समिति के अध्यक्षों से पूछा कि आपकी समिति के बैंक खाते में कितने रुपये हैं? तो वे नहीं बता सके, जबकि वे बैंक खाते का संचालन करने वाले हैं, समिति में कितने सदस्य हैं? समिति के काम क्या हैं? समिति के पैसे किन कामों में खर्च होते हैं? सरीखे सामान्य उत्तर नहीं दे पाते। जबकि कागजों पर वे वन सुरक्षा और वन विकास की योजनायें बना रहे हैं। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्राम वन समितियां बहुत जागरुक और सक्रिय हैं। मैंने जानना चाहा कि समितियों के खाते से लाखों रुपया नेताओं की यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए खर्च करना कौन सी जागरुकता है? जब वे बगलें झांकने लगे तो मैने कहा कि वन ग्राम समितियां आपके डिप्यूटी रेंजर के बंधुआ मजदूर से अधिक हैसियत नहीं रखतीं। बातों से और परतें न खुलने लगें इसलिए अन्य 'चतुर' अधिकारियों ने बात बदलना उचित समझा। थोड़ा लिखा बहुत समझा जाए। बीमारी की कुछ जांच रिपोटों के ये नतीजे बहुत ही कम हैं, इनसे सरकार में फैली बीमारी का अंदाज लगााकर इलाज करने से कुछ हो सकता है लेकिन होगा तब जब कोई इलाज करना चाहे। वरना जन और तंत्र के इन रिश्तों के साथ हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र तो हैं ही फिर यह अरण्य रुदन किस खुशी में?

खुशकिस्मत हैं, जिनके हिस्से दरख्त आए

विचार

गरिमा विजयवर्गीय
लेखक पत्रकार हैं।

गांव कितने भी समय बाद जाओ, कुछ चीजें हमेशा एक सी मिलती हैं, रत्ती भर भी अंतर नहीं। तारों भरा आसमान, ग्राम देवता की मढिया पर बैठे बब्बा, चूड़ी भरे हाथों से हैंडपंप से पानी निकालतीं गांव भर की बहुएं, सारंगी बजाते हर दरवाजे पर गीत गाता जोगी और गांव की चौपाल के बीचों-बीच आसमान से बातें करते नीम-पीपल।

शहर होने का मोह गांव को लील रहा है हालांकि, शहर अब भले ही स्वयं गाँव में विस्तारित हो रहे हैं, पर एक चीज़ जो तसल्ली दे रही है वो ये कि गांव जीवन बचाए हैं अब भी। शहरों में हमने पेड़ों के नामों पर आलीशान कॉलोनियां बना डालीं, गुलमोहर कॉलोनी, अमलतास कॉलोनी, नाका मदार नाम से कांक्रीट के जंगल बिछ गए, हर सुविधा है इन कॉलोनियों में, अगर कुछ नहीं दिखता तो बस एक अदद विशाल गुलमोहर, जिसकी छांव तपती गर्मी और चमकीली धूप को मानो हराने की ही ठान बैठी हो। कहीं नहीं दिखता जेठ की दुपहरियों में भी अपनी खूबसूरती से किसी को भी ठिठकने पर मजबूर करता अमलतास और नहीं दिखता सावन का श्रृंगार मदार और उसके हल्के बैंगनी फूल।

खुशकिस्मत हैं गांव, जिनके हिस्से 'स्मार्ट' होने का तमगा भले नहीं आया, पर उनके हिस्से विशाल दरख्त आए। गांव के हिस्से सिक्स लेन वाला विकास नहीं, उनके हिस्से तो बड़ मावस पर बड़ और आंवला नवमी पर आंवले को पूजने वाला कथित 'पिछड़ापन' आया। गांव के हिस्से दुनिया भर की ग्रीनहाउस गैस छोड़ते मॉल नहीं आए, पर उनके हिस्से कैत की छांव के नीचे बैठे ठाकुर बाबा और उनका चबूतरा आया। और सबसे बड़ी बात गांव के हिस्से एयरकंडीशंड कमरों में बैठकर वहां के विकास की योजना बनाते लोग नहीं, बल्कि आसमान छूते दरख्तों की एक डाल भी काटने पर गांव भर के बच्चों को डपट देते बुजुर्ग बब्बा आये।

एक अरसे बाद पापा पिछले साल अपने गांव दौसा जिले के बसवा पहुंचे। पैतृक घर भले ही खंडहर हो चला, पर पापा के कदम ठिठक गए बड़ के उस आसमान छूते पेड़ को देखकर, जिसकी छांव में लगभग 70 साल पहले बचपन बीता उनका। उसी दिन जाना, केवल प्राणवायु ही नहीं देते, स्मृतियों में भी प्राण फूंक देते हैं दरख्त। कमोबेश यही स्थिति मेरे श्वसुर की अपने पैतृक गांव सनाई जाकर दिखती है। पुराने पेड़ों से जुड़ी स्मृतियां टटोलने और वृक्षों की उम्र का अंदाज़ लगाने के लिए उनकी 'एनुअल रिंग्स' गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती पापा को।

मूक वृक्षों के साथ घर के अपने बुजुर्गों के इस सजीव से रिश्ते को देख बस एक ही विचार आता है मन में। शहरों में जिन बचे-खुचे पेड़ों की छांव में बचपन के कुछ खेल खेल रहे हैं बच्चे, कुछ सालों बाद अपने शहर लौट कर क्या इन पेड़ों से जुड़ी अपनी स्मृतियों को टटोलने का अवसर पा सकेंगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कॉकरोच बनाम डायनासोर!

व्यंग्य

डॉ.महेन्द्र अग्रवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

कॉकरोच हमारी पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें डायनासोर के ज़माने का माना है। इनका प्रताप देखिए कि डायनासोर जैसे विशालकाय जीव लाखों वर्ष पूर्व नष्ट हो गये पर इनका वजूद व जलवा अभी भी बना हुआ है। शायद किसी शायर ने इनके लिए ही लिखा हो कि -क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।हो सकता है कि इनकी हाय से ही डायनासोर का विनाश हुआ हो। क्योंकि गरीब की बद्दुआ की तरह इनकी हाय भी जल्दी फलित होती है। महाभारत काल की एक कथा है कि गांधारी ने एक बार गलती से एक गर्भवती तिलचट्टे पर पैर रख कर उस माँ के साथ उसके सौ अंडों को कुचल दिया। तभी उन्हें श्राप मिल गया था कि वह भी इसी तरह अपने सौ बेटों को मरता हुआ देखेंगी और शोक मनायेंगी। और वाकई महाभारत में यही हुआ।

सुना और देखा तो आपने भी होगा,आजकल कॉकरोच पार्टी की भारी धूम है। अभी तक इन्हें पार्टी मनाते देखा था, पार्टी बनाते पहली बार देख रहे हैं इसलिए आश्चर्य होना स्वाभाविक है। वह भी इतनी फुर्ती से,रातों-रात,वैश्विक स्तर पर क्या यह पूर्व नियोजित है? या नामानुरूप सैंकड़ों की संख्या में जन्म लेना प्रकृति का वरदान है। जैसे युद्ध में रक्त की हर बूंद से नए जीव का जन्म हो जाये।

कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा भी कहते हैं ।यह आर्थोपोडा संघ में आने वाला अकशेरुकी मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाला एक कीट है।यह हमारी नई पीढ़ी की तरह निशाचरी है।यह स्वभाव से सर्वहारी है अर्थात शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। इसका शरीर ऊपर से कठोर आवरण से ढका रहता है किन्तु अंदरूनी हालत से सब वाक़िफ़ हैं। इसका शरीर चपटा भले ही हो पर यह अपनी जुड़ी हुई छह टांगों और सर पर लगे दो लंबे एंटीना से अलग ही पहचाना जाता है। यह स्वच्छता की कमी और खुले में बिखरे खाद्य -अखाद्य पदार्थों से फैलते हैं। मतलब हमारी अपनी व्यवस्था की खराबी और लापरवाही इन्हें निमंत्रण देती है कि आओ हमारे घर में और फैल जाओ। मतलब समझ रहे हो न बाबू? सामान्यतः यह छुपे हुए रहते हैं अतः अपनी नजरों के स्तर पर देश या विदेश में कहीं भी छुपे हो सकते हैं। होने को यह छुपे रुस्तम भी हो सकते हैं। यह अक्सर किचन में रहकर अपना परिवार बढ़ाते हैं और वहीं सिंक में जाकर अपनी पार्टी मनाते हैं। जब इनकी संख्या बहुसंख्यक होने की श्रेणी में आ जाती है तो यह वहीं रातोंरात अपनी पार्टी बना लेते हैं और मस्ती में पड़े रहते हैं।फिर इसके सदस्य दूसरों की हवा खराब करते हुए सर्वत्र निर्बाध पूरे क्षेत्र में घूमते हैं।

महिलाएं और कुछ पुरुष इनसे बहुत डरते हैं अतः महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें मारने के लिए एक कंपनी ने अलग से लाल हिट्स का आविष्कार किया है जो इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लगातार विज्ञापन देती रहती है। दूसरे शब्दों में आईटी के व्यापक प्रयोग से इनका एनकाउंटर कराती है और यह अगले ही दृश्य में बेहोश या मरे पड़े हुए दिखाई देते हैं। जो बच निकलते हैं वह बहुत डरते हैं और फिर इधर-उधर भागते हुए दिखाई देते हैं यानी कमजोर साबित होते हैं।

इनकी विशेषता है कि सर कटने के बाद भी यह सात आठ दिन जिंदा रह लेते हैं क्योंकि सर कटने के बाद भी इनका खून बाहर नहीं निकलता।लेकिन बिना मुंह के पानी न पीने के कारण डिहाइड्रेशन से इसकी मौत होती है अर्थात सोशल एकाउंट बंद करने से क्या होगा? जिस दिन फेसबुक इंस्टाग्राम पर पानी मिलना बंद हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन से इनकी मौत हो सकती है। फिर भी उम्मीद है कि बैन लगने या अन्य बंदिशों के बाद भी सोशल मीडिया पर इनका हल्ला अगले कुछ दिन बना रहेगा। हल्ला तो अब इसलिए भी रहेगा कि इनकी प्रतिस्पर्धा फिर से डायनासोर से है। देखें अबकी क्या होता है? ये बचते हैं या डायनासोर?

हिंदी पत्रकारिता दिवस विशेष

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र,कोलकाता।

पत्रकारिता का चरित्र हमेशा प्रतिरोधी रहा है

अखबार वितरण में अंग्रेजों द्वारा डाक शुल्क में लगातार वृद्धि और छूट न दिए जाने के कारण इसका 79वां और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित हुआ था। इस अखबार के पहले अंक की 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थीं। इस समाचार पत्र के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का आयोजन लाज़मी है लेकिन उसी के साथ हमारे विमर्श के केंद्र में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या का लगातार घटना,उनके प्रतिरोधी स्वरूप का लगातार ह्रास,बड़े-बड़े मीडिया घरानों का नियंत्रण और उनसे एक ही विचारधारा का प्रचार-प्रसार करवाया जाना भी शामिल होना चाहिए।

भारत में इस वर्ष उदंत मार्तण्ड समाचार पत्र का द्विशताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जो देश का पहला हिंदी समाचार पत्र था। 'उदंत मार्तण्ड' का शाब्दिक अर्थ 'समाचार सूर्य' था। यह 30 मई 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होने वाले इस साप्ताहिक अखबार में हिंदी भाषा के साथ बृज और अवधी भाषा के शब्दों का भी मिश्रण होता था। अखबार वितरण में अंग्रेजों द्वारा डाक शुल्क में लगातार वृद्धि और छूट न दिए जाने के कारण इसका 79वां और आखिरी अंक दिसंबर 1827 में प्रकाशित हुआ था। इस अखबार के पहले अंक की 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थीं। इस समाचार पत्र के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता के 200वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का आयोजन लाज़मी है लेकिन उसी के साथ हमारे विमर्श के केंद्र में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या का लगातार घटना,उनके प्रतिरोधी स्वरूप का लगातार ह्रास, बड़े-बड़े मीडिया घरानों का नियंत्रण और उनसे एक ही विचारधारा का प्रचार-प्रसार करवाया जाना भी शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 'आरएसएफ' जिसे 'रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स' कहा जाता है उसकी चिंताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह पत्रकारिता पर नजर रखने वाली एक संस्था है। इसके अनुसार दुनिया के कई हिस्सों में पत्रकारिता की स्थिति में चिंताजनक गिरावट आई है। इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स) की 30 अप्रैल 2026 में जारी सूची के अनुसार 180 देशों में भारत 157वें स्थान पर है। यह सूचकांक सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा जैसे कई मानकों पर आधारित है और भारत के इन सभी क्षेत्रों में अलग-अलग स्कोर दिए गए हैं। इसके पूर्व वर्ष 2025 में 151वें स्थान पर था। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश या कहें छोटे देश इस सूचकांक में भारत से ऊपर हैं। पाकिस्तान-153,भूटान-150, नेपाल-87,श्रीलंका-134,बांग्लादेश-152 वे स्थान पर है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नार्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन हैं और सबसे निचले पायदान पर सऊदी अरब, ईरान,चीन,उत्तर कोरिया हैं। भारतीय पत्रकारिता की विकास यात्रा के तीन चरण और उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को संक्षिप्त रूप में साझा कर रही हूं। भारतीय पत्रकारिता का पहला चरण 'राष्ट्रवाद बनाम उपनिवेशवाद' का यह चरण 1947 तक चला जो दो ध्रुवों में बँट हुआ था,एक औपनिवेशिक शासन का समर्थक मतलब सत्ता समर्थक और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत लोगों का समर्थक और सत्ता विरोधी मीडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना का संचार करने के लिए हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कार्य होने लगा था जिसने जनचेतना का विकास किया,साथ ही आलोचना का एक स्पेस भी विकसित किया था। लार्ड लिटन ने भाषायी पत्रों के स्वर और तेवर को अपने लिए खतरनाक मानकर उसे खारिज करने के लिए 'देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 बनाया था। यह अधिनियम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना था और ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया खासकर प्रिंट मीडिया को रोकाना था। इस अधिनियम का सबसे नकारात्मक पक्ष यह था कि इसके अनुसार देशी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और साथ ही इसमें अपराधी के अपील करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत अनेक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। इस एक्ट का भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में भी जमकर विरोध हुआ था। 1880 में ग्लैडस्टोन के सत्ता में आने के बाद परिस्थितियां बदल गई और गवर्नर जनरल लार्ड रिपन ने इस एक्ट को निरस्त कर दिया। इसके बाद 1898 में भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन हुआ और दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई। वर्ष 1903 में भारतीय 'गुप्त बात अधिनियम 1888' में संशोधन करके सिविल बातों को भी सैनिक,नौसैनिक मामलों के समान बना दिया गया। बंग-भंग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और लोकमान्य तिलक की उग्रराष्ट्रवादी नीति से भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप और तीव्र और उग्र हो गया था। जिसके दमन के लिए

समाचारपत्र अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को लागू किया गया। भारतीय समाचारपत्र (संकट कालीन शक्तियां) अधिनियम 1931 लागू किया गया। इस दौरान कई बड़े-बड़े राजनेताओं ने भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का संपादन कार्य किया।

मीडिया का दूसरा चरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ हुआ और अस्सी के दशक तक चला। इस लंबी अवधि में मीडिया के प्रसार और गुणवत्ता में जबरदस्त वृद्धि हुई। मीडिया के विभिन्न रूप भारत को आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनाने के लक्ष्य के इर्द गिर्द गढ़ी गई। इसी दौरान टीवी का आगमन हुआ। रेडियो और टीवी की कमान सरकार के हाथों में रही,जबकि प्रिंट मीडिया निजी क्षेत्र के हाथों में चला गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 से सरकार और मीडिया के रिश्ते बुनियादी तौर पर बदल गए। भारतीय मीडिया से ब्रिटिश शासन की पाबंदियां हटा दी गई और ब्रिटिश समर्थक अखबारों का नियंत्रण भारतीय हाथों में आ गया। मार्च 1947 में समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया गया जिसे मौलिक अधिकारों के आलोक में प्रेस कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया। इस समिति के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता बाधित करने वाले कानूनों को समाप्त कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में मीडिया ने राजनीतिक नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिक भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। सरकार के द्वारा 1952 और 1977 में दो प्रेस आयोग भी गठित किए गए। 1965 में एक संविधानगत संस्था प्रेस परिषद की भी स्थापना की गई। 1956 में रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट के तहत प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई। आपातकाल के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप थोप दी गई और प्रेस परिषद को भंग कर दिया गया तब भारतीय प्रेस ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता को महसूस किया और प्रतिरोध किया।

अस्सी का दशक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए चलाए गए संघर्षों का दशक साबित हुआ। इन संघर्षों से भाषाई पत्रकारिता का विकास हुआ। संघर्ष के बाद निर्मित नई परिस्थिति का सबसे ज्यादा लाभ हिंदी,पंजाबी, गुजराती,बांग्ला, असमिया और दक्षिण भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को हुआ। इसी दौरान भाषाई क्षेत्रों में नये पत्रकारों का उदय भी हुआ। राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रसार संख्या वाले पहले दस समाचार पत्रों में अंग्रेजी का महज एक ही समाचार पत्र रह गया और वह भी नीचे से दूसरे स्थान पर है। मीडिया के विकास का यह द्वितीय चरण था जो अस्सी के दशक तक निर्बाध रूप से चलता रहा। नब्बे के दशक में भूमंडलीकरण के आगमन से मीडिया के तीसरे चरण की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। इस दौर में निजी क्षेत्र में 24 घंटे चलने वाले उपग्रहीय टीवी चैनल और एफ.एम. रेडियो चैनलों का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ है। मीडिया का आकार और उसकी पहुंच लोगों तक अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी है। नयी मीडिया की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। नई प्रौद्योगिकी से भारत में भी वही स्थिति निर्मित हो गई है जिसे पश्चिम में 'मीडिया स्फियर' कहा जाता है। इस दौरान अभिजात्य ताकतों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इजाद किया और 'नागरिकों की भूमिका' को 'उपभोक्ता की भूमिका' में तब्दील कर दिया। भारत में वर्ष 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के अंत तक वह बड़ी संख्या में लोगों की निजी और व्यावसायिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। नयी मीडिया प्रौद्योगिकी के जरिये मोबाइल फोन के मार्फ़त उसकी पहुंच अधिक लोगों तक हो गई। जिससे मीडिया का दायरा विस्तृत और विविध बन गया। इसके आगोश में सार्वजनिक जीवन के अधिकतर आयाम समा गए। जिससे एक अलग मीडिया स्फियर का उदय हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल पहले मनोरंजन और सूचनाओं के आदान-प्रदान तक सीमित था। लेकिन अब इनका इस्तेमाल पब्लिक अपने हितों और प्रतिरोध के लिए कर रही है। सोशल मीडिया पर भी नियंत्रण के नए-नए शिकंजे कसे जा रहे हैं लेकिन हर नया प्रतिरोध अभिव्यक्ति के तरीके खोज ही लेता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि हम उन सभी छोटे और बड़े,स्त्री और पुरुष पत्रकारों के साथ खड़े हों जो सच को उजागर कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं और इसके कारण उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है, मारने की धमकियां मिल रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है जो ऑनलाइन उत्पीड़न है,उन पर हमले हो रहे है,मुकदमे चलाए जा रहे हैं और पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इन सब के विरुद्ध सत्याग्रह नागरिक प्रतिरोध की भी आवश्यकता है जिससे हिंदी पत्रकारिता की प्रतिरोध की संस्कृति को बचाया और बनाया रखा जा सके। पत्रकारिता का स्वरूप हमेशा से ही प्रतिरोधी रहा है,जरूरत इसके चरित्र को, इसके अस्तित्व को बचाये रखने की है।

हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी

प्रो.संजय द्विवेदी

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।

अब यहां से कहां जाएं हम ?

हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी (200 वर्ष) पर समारोहों की धूम है। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, रायपुर, कानपुर से लेकर अनेक शहरों और विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभागों पर विमर्श व संवाद के अनेक आयोजन हो रहे हैं। जाहिर है हिंदी का गौरव और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है। उसकी लोकस्वीकृति बढ़ी है। वह भारत में मीडिया, मनोरंजन जगत और वोट मांगने की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी देश के ताकतवर प्रधानमंत्री से लेकर सामान्यजन तक की भाषा बन गयी है। राजनीतिक संचार की सबसे बड़ी भाषा वह पहले से थी किंतु नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की केंद्रीय उपस्थिति में वह सत्ता की भी भाषा बन गयी है। जाहिर है उसके मीडिया का भी अपना जलवा है। आज वह सत्ताधीशों की प्रिय भाषा है, जनभाषा तो वह पहले से थी।

क्या हमारी भाषा बचेगी?

द्विशताब्दी वर्ष का उत्सव मनाते हुए कई सवाल मथ रहे हैं। हिंदी प्रेमियों के सत्तारूढ़ होने, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण हिंदी की ताकत सामने दिख रही है। किंतु हमें उन सवालों पर भी सोचना होगा जिससे हमारी पत्रकारिता और मीडिया को शक्ति मिलती है। पत्रकारिता को शक्ति देने वाली पहली ताकत है 'भाषा'। क्या हमारी आनेवाली पीढ़ी हिंदी के साथ सहज है? वह पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना हिंदी में कर रही है? उसकी शिक्षा का माध्यम क्या धीरे-धीरे अंग्रेजी नहीं हो गयी है? ऐसे कठिन समय में हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती है। हिंदी के पाठक ही न होंगें तो हिंदी के प्रिंट माध्यमों का भविष्य क्या है? इसी तरह हिंदी सुनी जाने वाली भाषा में बदल रही है। उसके गंभीर अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं और अन्य माध्यमों के सामने गहरा संकट है।

अकादमिक विमर्श की भाषा बनने की चुनौती

हिंदी का उपयोग बड़ी मात्रा में मनोरंजन, राजनीतिक संचार या बाजार में ही हो रहा है। गंभीर अकादमिक विमर्श की भाषा बने बिना उसे लंबे समय तक टिकाए रखना कठिन होगा। जनसंचार की वह सबसे लोकप्रिय भाषा हो सकती है, किंतु ज्ञान-विज्ञान के हर अनुशासन की भाषा बने बिना उसे वह महत्व नहीं मिल सकता, जो दुनिया की ताकतवर भाषाओं को मिल रहा है। मीडिया लोकप्रिय को साधता है, सबसे संवाद करता है, मनोरंजन करता है, सूचना देता है। किंतु भाषा के अनेक रूप हैं जिनमें भाषा को साबित करना होता है। ऐसे में गंभीर प्रकाशनों की हालत अच्छी नहीं है। हिंदी विमर्श की नहीं, प्रचार की भाषा ज्यादा बन गयी है। जिस तरह के गंभीर अखबार और पत्रिकाएं आज भी कम पाठक संख्या के बावजूद अंग्रेजी भाषा के पास हैं, हिंदी के पास नहीं हैं। हिंदी वैचारिक दारिद्रय से जूझ रही भाषा है। जिसके पास गौरवशाली अतीत है, बहुत आत्मविश्वास है। किंतु गहराई कम हो रही है। हम लोकप्रियता को साधने वाली पत्रकारिता तक सीमित हो रहे हैं। जिसमें गंभीर अनुसंधान, माटी की सुगंध कम होती जा रही है।

कृत्रिम बुद्धिमता से जूझती भाषा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में जब भाषाएं तेजी से मशीनीकृत हो रही हैं। हिंदी अपना रुप, रस, गंध और आस्वाद गवां सकती है। तमाम माध्यमों की एआई पर बढ़ती निर्भरता भाषा के साथ खिलवाड़ जैसा ही है। एआई के मशीनी-तकनीकी इस्तेमालों से आगे जब एआई, भाषा की ओर बढ़ रही है तो उसकी सीमाएं बहुत स्पष्ठ हैं। भाषा का समाज में फलना-फूलना और विकसित होना बहुत सहज और स्वाभाविक है। किंतु मशीनों द्वारा बन रही भाषा क्या रूप लेगी कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चिंता इसलिए भाषा की है क्योंकि भाषा ही नहीं बचेगी तो भाषा पर आधारित विधाएं जिनमें पत्रकारिता भी एक है कैसे बचेगी।

ऐसे कठिन समय में जब मीडिया में मूल्यबोध,भाषा की शुचिता के सवाल बेमानी लगने लगे हों, गंभीरता के साथ इस विधा में काम करनेवालों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। स्कूलों से लेकर पूरे अकादमिक जगत में हिंदी लगभग बहिष्कृत भाषा बन गयी है। आने वाले दिनों में क्या हिंदी सिर्फ बोलने की भाषा रह जाएगी जैसा वो पहले कभी थी। हमारे यशस्वी संपादकों बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, सखाराम गणेश देउस्कर, माधवराव सप्रे जैसे नायकों की बदौलत आज हम यहां तक पहुंचे हैं। समाज में अलग-अलग तरह से बरती जा रही भाषा ने न सिर्फ अनुशासन और व्याकरण पाया बल्कि वह शानदार गद्य की भाषा बनी। हिंदी पत्रकारिता के संपादकों का यह योगदान हमें पता है कि कैसे उन्होंने एक शानदार भाषा हमें सौंपी। यह ऐसी भाषा बनी जो सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं थी, समाज जीवन के विविध अनुशासनों को व्यक्त करने वाली भाषा थी। उसकी ताकत दिखने लगी। पत्रकारिता में छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, हंस, प्रभा, कल्पना जैसी पत्रिकाओं ने जो किया उसकी मिसाल खोजने पर नहीं मिलेगी। भाषा का आत्मविश्वास और सार्मथ्य हिंदी पत्रकारिता ने उसे अनुभव करवाया।

संकल्प से मिलेगी सिद्धि

200 साल पूरे करने के बाद अब हमें कुछ संकल्प लेने ही चाहिए। पं. युगलकिशोर शुक्ल ने उदंत मार्त्तण्ड के रुप में जो दीप जलाया, उसे हमें प्रज्ज्वलित रखना है। यह कर्तव्य और उत्तराधिकार दोनों हमें मिला है। हम अपनी भाषा को कैसे बचाएं। कैसे उसे हर अनुशासन की भाषा बनाएं यह संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अकादमिक, प्रशासनिक, न्याय व्यवस्था, वित्त और व्यवसाय तक विविध क्षेत्रों में हिंदी का प्रभावी हस्तक्षेप अभी शेष है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता इसे मिलकर ही कर सकते हैं। इससे स्वत्व की पहचान होगी और भारतबोध प्रखर होगा। हमें अपने लोगों को न्याय दिलाना है तो यह उनकी अपनी भाषा में ही संभव है।

वैचारिक साम्राज्यवाद के मुक्ति इन्हीं प्रयासों से मिलेगी। यह सिर्फ भाषा प्रेम का सवाल नहीं, भारतप्रेम और सामाजिक न्याय का भी विषय है। अपनी भाषाओं में बोलता, पढ़ता, सुनता, सीखता भारत अभी भी प्रतीक्षित है। मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। हमें पता है कि आज के युग में जिस तरह मीडिया का विस्तार हुआ है, भूगोल की सीमाएं डिजिटल मीडिया के नाते टूट गई हैं। उसमें जो श्रेष्ठ होगा वही टिकेगा। अपनी भाषा में हम श्रेष्ठतम सृजन करें। हिंदी को इतना ताकतवर बनाएं कि दुनिया के ज्ञान क्षेत्र में सक्रिय जन हमारी पत्रकारिता से संदर्भ ग्रहण करें। उधार और जूठन पर आधारित लेखन और पत्रकारिता का कोई मूल्य नहीं है, इसे हम जानते हैं। गंभीर रिपोर्टिंग और गंभीर विश्वेषण आज की जरुरत है। इससे ही हमें मौलिक सृजनकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाएगा। भारत का विचार श्रेष्ठता का विचार है, विश्वमंगल का विचार है। हमारी पत्रकारिता अगर इसकी वाहक बन रही है तो यह बात हमारे संकल्पों और दृढ़ करेगी। 200 साल पूरे करने की बधाई देते हुए मीडिया जगत से यह आग्रह भी है कि वे हिंदी पत्रकारिता के ध्वज को गुणवत्ता के आधार पर और ऊंचा ले जाएगें।

हिंदी पत्रकारिता दिवस पर विशेष

प्रो. मनोज कुमार

लेखक पत्रिका 'समागम' के संपादक हैं।

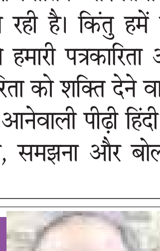

माना कि अंधेरा घना है, पर दीया जलाना कहाँ मना है

हिंदी पत्रकारिता कहाँ दो सौ साल पहले अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और आज हम अपने ही लोगों से लोहा ले रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की साख को बचाने के लिए पत्रकारिता संघर्ष कर रही है और यह संघर्ष अनवरत चलने वाला है। हर सत्ता के लिए पत्रकारिता खतरे की घंटी हुआ करती थी और आगे भी रहेगी। यह जानकर अच्छा लगता है कि चाहे पत्रकारिता में जितनी गिरावट आ गई हो, हर कोई अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पत्रकारिता से भयभीत रहता है। दो साल की हिंदी पत्रकारिता की यही साख है और पूँजी भी। हालाँकि इन दो सौ सालों में बहुत कुछ बदला है। पत्रकारिता की तकनीक हाशिये पर है और हम तकनीक की पत्रकारिता करने लग गए हैं। इस बदलाव से हिंदी पत्रकारिता का यह संक्रमण काल है। यह बात पत्रकारिता में रचे-बसे नए और पुराने दोनों पीढ़ियों को मान लेना चाहिए। वर्तमान समय में चारों तरफ इसी बात पर चर्चा हो रही है कि हिंदी पत्रकारिता एआई और चैटजीपीटी से कैसे निपटे? संकट बड़ा है तो इसका समाधान भी हमें ही तलाश करना होगा। हिंदी पत्रकारिता पर यह संकट पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है।

दो सौ साल की पत्रकारिता का स्मरण करते हुए जब हम पंडित युगल किशोर का स्मरण करते हैं, उदंत मार्त्तण्ड का स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अभिमान से भर उठते हैं और दो सौ साल बाद की पत्रकारिता की सीरत देखते हैं तो कम से कम अभिमान तो होता ही नहीं है। दो साल में हिंदी पत्रकारिता के पास बताने के लिए बहुत कुछ था लेकिन हमने बहुत कुछ पाने के लिए उसे खो दिया। हिंदी पत्रकारिता कहाँ दो सौ साल पहले अंग्रेजों से लोहा ले रही थी और आज हम अपने ही लोगों से लोहा ले रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की साख को बचाने के लिए पत्रकारिता संघर्ष कर रही है और यह संघर्ष अनवरत चलने वाला है। हर सत्ता के लिए पत्रकारिता खतरे की घंटी हुआ करती थी और आगे भी रहेगी। यह जानकर अच्छा लगता है कि चाहे पत्रकारिता में जितनी गिरावट आ गई हो, हर कोई अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पत्रकारिता से भयभीत रहता है। दो साल की हिंदी पत्रकारिता की यही साख है और पूँजी भी। हालाँकि इन दो सौ सालों में बहुत कुछ बदला है। पत्रकारिता की तकनीक हाशिये पर है और हम तकनीक की पत्रकारिता करने लग गए हैं। इस बदलाव से हिंदी पत्रकारिता का यह संक्रमण काल है। यह बात पत्रकारिता में रचे-बसे नए और पुराने दोनों पीढ़ियों को मान लेना चाहिए। वर्तमान समय में चारों तरफ इसी बात पर चर्चा हो रही है कि हिंदी पत्रकारिता एआई और चैटजीपीटी से कैसे निपटे? संकट बड़ा है तो इसका समाधान भी हमें ही तलाश करना होगा। हिंदी पत्रकारिता पर यह संकट पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है। ऐसे संकट आते-जाते रहेंगे लेकिन यह भी भरोसा है कि समय के साथ इसका समाधान भी हम सब तलाश कर ही लेंगे।

लंबे संघर्ष के बाद भारत ने स्वाधीनता हासिल किया तो इसमें हिंदी पत्रकारिता की अहम भूमिका थी। अनेक संकटों और झंझावतों से गुजरते हुए अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा वाली हिंदी पत्रकारिता पर अब जिम्मेदारी थी नव भारत निर्माण में चौकीदार बनने की। देश में नवाचार हो रहा था लिहाजा उस समय काल और परिस्थिति के अनुरूप बजट भी आ रहा था। पैसों की बंदरबाट की कहानी शायद उसके जन्म से है। कल भी था और आज भी है। खैर, तब हिंदी पत्रकारिता ने जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह किया और तब भी अनेक घपले-घोटाले को बेनकाब किया। इस भूमिका के लिए हिंदी पत्रकारिता की पीठ सबने थपथपायी लेकिन भीतर से सत्ता का नाराज होना लाजिमी था। प्रतिपक्ष के लिए तब हिंदी पत्रकारिता की जवाबदारी नैतिक और राष्ट्रहित में होता था लेकिन यही प्रतिपक्ष जब सत्तासीन होता है तो पत्रकारिता उसकी बैरी हो जाती है। सत्ता के साथ पत्रकारिता का रिश्ता वैसा ही है, जैसा की नदी के दो पाट। चलेंगे साथ-साथ लेकिन मिलेंगे कभी नहीं। खरामा-खरामा साल 47 से साल 75 तक पहुँच गए और यही वह साल था जब हिंदी पत्रकारिता का गला घोंटने की साजिश की गई। तानाशाह शासन व्यवस्था ने पत्रकारिता पर पहरे बिठा दिए। शब्द-शब्द सरकार की निगरानी में छपने लगे। तमाम बंदिशों के बाद भी पत्रकारिता कहाँ हार मानने वाली थी। तानाशाह सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। विरोधस्वरूप संपादकीय पृष्ठ कोरा छोड़ दिया गया। और भी विरोध के अपने तरीके अपनाए गए। पत्रकारिता का यह स्वाभिमान आज भी शेष है। हालाँकि यह भी सच है कि इसी दौर में यह वाक्य चल पड़ा कि- तानाशाह शासन ने कहा कि घुटने के बल चलो तो लोग रेंगने लगे। सौ तो नहीं, अंशभर यह उस समय की सच्चाई है।

असल चेहरा और पत्रकारिता की साख गिरने का समय साल 75 के बीत जाने के बाद दिखने लगा। पत्रकारिता, मीडिया का स्वरूप धारण करने लगा और मीडिया को उद्योग का दर्जा दिए जाने की माँग उठने लगी। मिशन से मीडिया और मीडिया से उद्योग बन चली पत्रकारिता आहिस्ता-आहिस्ता रोजगार का चेहरा बनने लगी। एक तरफ पत्रकारिता मीडिया बन गई तो दूसरी तरफ पेशेवर पत्रकार तैयार करने के लिए उद्योग की तरह ही मीडिया शिक्षा के संस्थान कुकुरमुत्ते की भाँति उठ खड़े हुए। हर की अपनी खासियत, हरेक के अपने दावे। पत्रकारिता को औजार बना दिया गया। मीडिया शिक्षा तब और बढने् लगा जब पत्रकारिता की तकनीक हाशिये पर जाने लगी और तकनीक की पत्रकारिता होने लगी। अबके समय में आपकी दक्षता विचारों की नहीं, किसी की पीड़ा को देखकर उसे न्याय दिलाने की नहीं, तकनीक के माध्यम से क्या स्टोरी बनायी जा सकती है और इसमें कौन कितना दक्ष होगा, यह मीडिया शिक्षा तय कर रही है। अपनी 45 सालों की पत्रकारिता में मेरे गुरुजनों ने सिखाया कि पत्रकारिता दिल से होती है लेकिन मेरी बाद की पीढ़ी के लिए पत्रकारिता दिमाग का है। रही-सही कसर आज की एआई और चैटजीपीटी जैसे तकनीक ने पूरा कर दिया है। बरसों पहले मर चुकी संपादक संस्था के नए कारकून मोबाइल पर अपने डिमांड के अनुरूप स्टोरी लिखने को बोलते हैं और चट से 'बोलो मेरे आका' के अंदाज में वह सबकुछ दे देता है, जो आपको चाहिए। तकनीक की पत्रकारिता का यह खतरा हम सबके लिए खतरा बन चुका है। अब एक ही रास्ता है कि हम खुद को इस तकनीकी पत्रकारिता के ढाँचे में ढाल लें या इससे बाहर हो जाएँ। कोई तीन दशक पहले फोटोटाइप सेटर और इसके बाद कम्प्यूटर आया तो जो इसके हमसफर हो गए, वे तो बच गए लेकिन अनेक की पत्रकारिता आले पर रख दी गई। अब ओटले की पत्रकारिता होने लगी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कभी समाज भरोसे के साथ कहता था कि- पढ़ा नहीं, फलां अखबार में छपा है और आज वही कहते हैं कि एक बार खबर को जाँच लेना। इन सबके बावजूद हमारे पुरखा बालकवि बैरागी जी कि यह पंक्ति बरबस याद आ जाती है- माना कि अंधेरा घना है।

धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के 6 खिलाड़ी चयनित

धार। इंदौर डिविजन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिनांक 4 जून से 15 जून तक अंडर 18 का क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर इंदौर में आयोजित किया जा रहा है इसमें धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के 6 खिलाड़ी आदित्य सक्सेना ,नीलेश पटेल ,अरमान खान ,सुदीप वर्मा ,युवराज सिंह व प्रवीण राठौर का चयन हुआ है। प्रशिक्षण अंकित पाराशर चीफ कोच द्वारा दिया जाएगा चयनित खिलाड़ी पाराशर जी के मोबाइल नंबर 99 77 80 41 00 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस उपलब्धि पर धार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन करन सिंह पंवार, अध्यक्ष प्रदीप जोशी , सचिव राजेंद्र सिंह चौहान ,धीरेंद्र दिघे, राम गोपाल शर्मा ,महेंद्र सुर्वे ,प्रमोद फाटक, प्रमोद शर्मा ,अंबालाल पाटीदार कपिल यादव ,शैलेंद्र जोशी, कुशल शर्मा आदि पदाधिकारियों ने बधाई प्रेषित की।

जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर की जैन साधु संतों की सुरक्षा की माँग

धार। धार सकल जैन समाज द्वारा विगत दिवस रीवा में एक कार चालक द्वारा लापरवाही से कार चलाते हुवे दो दिगम्बर जैन साध्वियों को टक्कर मार कर घायल कर दिया गया इस दुर्घटना में दोनों साध्वियों का देवलोक गमन हो गया जिससे पूरे भारत वर्ष की जैन समाज में आक्रोश है। जैन समाज द्वारा ज्ञापन दे कर घटना की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाने की माँग करते हुए भविष्य में जैन संतो के विहार पर प्रशासन द्वारा समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस द्वारा सुरक्षा व सहयोग की मांग की गई। इस अवसर पर सकल जैन समाज के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहेद्य ज्ञापन का वाचन समाज अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल ने किया ज्ञापन एसडीएम राहुल गुप्ता द्वारा ले कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

22 से 24 मई तक चला गिद्धों की गणना का कार्य

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले में ऑनलाइन एप के जरिए 3 दिन तक चली गिद्धों की गिनती पूरी हो गई है। ग्रीमष्कालीन सर्वे के दौरान तीन दिन में कुल 6 गिद्ध मिले हैं, जबकि पिछली गणना में एक भी गिद्द जिले में नहीं मिले थे। बताया जा रहा है कि गिद्दों की गिनती के लिए वन विभाग द्वारा शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन सर्वे किया जाता है। शीतकालीन सर्वे फरवरी माह में किया गया था, वहीं ग्रीष्मकालीन सर्वे 22 मई से 24 मई तक चला। इस दौरान उत्तर ऽऔर दक्षिण वन मंडल अंतर्गत तीन प्रजातियों के 6 गिद्द मिले है। हालांकि 10 साल पहले यहां महज दो गिद्ध मिले थे। जिसके बाद यह डेटा निरंक पाया गया है। अभी बैतूल वन वृत्त के सभी बीटों के वन रक्षकों ने गिद्धों की गणना की है। जिसमें 123 पश्चिम, 140 उत्तर और 180 दक्षिण बीट में एक साथ सर्वे किया गया। गिद्द गणना के नोडल अधिकारी जितेन्द्र अवासे ने बताया कि गिद्धों की गणना कर एप में उसकी जानकारी दर्ज की है। जानकारों के अनुसार धरती के सफाई दूत कहे जाने वाले गिद्दों की संख्या जिले में बुरी तरह घटती जा रही थी। जिसके पीछे प्रमुख कारण बैतूल जिले का वातावरण और यहां गिद्धों के लिए अनुकूल परिवेश न होना माना जा रहा है। दूसरी तरफ पर्यावरण विज्ञानी इसे कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को भी कारण मान रहे हैं। गिद्द गणना के नोडल अधिकारी जितेन्द्र अवासे

ने बताया कि जिले में हर साल दो बार गिद्धों की गणना की जाती है। ग्राष्मकालीन गणना 22 से 24 मई तक हुई, जिसमें 6 गिद्द मिले है।

जिले में मिली गिद्धों की तीन प्रजातियां- जिले में गिद्धों की गणना के लिए हुए ग्रीष्मकालीन सर्वे के दौरान तीन प्रजातियों के 6 गिद्दो को निवास जिले में है। इसमें एक लॉन्ग बिल्ड इसे भारतीय गिद्द भी जाता है, जो पर्यावरण को साफ रखने वाले महत्वपूर्ण प्राकृतिक सफाईकर्मी है और खुले मैदानी इलाकों, खेतों और चट्टानी क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी प्रजाति इजिपियन गिद्द जिसे सफेद गिद्ध भी कहा जाता है, इनकी भी जिले में मौजूदगी पाई गई है। वहीं तीसरी प्रजाति सिनेरियस गिद्द (एजीपियस मोनाचस), जिसे यूरेशियन ब्लैक गिद्ध भी कहा जाता है, यह आकाश का एक विशालकाय पक्षी है। अपने प्रभावशाली आकार के लिए प्रसिद्ध, यह प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा गिद्ध और विश्व स्तर पर सबसे बड़े और भारी शिकारी पक्षियों में से एक है, जिसके पंखों का फैलाव आश्चर्यजनक रूप से 3 मीटर तक होता है।

उत्तर और पश्चिम वन मंडल में मिले 3-3 गिद्ध- जिले के उत्तर और पश्चिम वन मंडल में तीन-तीन गिद्द मिले है, वहीं दक्षिण वन मंडल क्षेत्र अंतर्गत गिद्धों की संख्या निरंक पाई गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर वन मंडल में 3 और पश्चिम वन मंडल में 3 गिद्ध मिले हैं। कुल तीन प्रजातियों के 6 गिद्द जिले में पाये गये है। गिद्ध गणना के नोडल अधिकारी जितेन्द्र आवसे ने बताया कि पहले गिद्धों की गणना कागजों पर होती है, लेकिन इस बार एप के माध्यम से गिद्दो की गणना की गई। श्री आवसे ने बताया कि पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ गिद्धों की गणना की गई। इसमें सुखद यह रहा कि पूरे मध्यप्रदेश में 15 हजार से अधिक विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध मिले है। बैतूल में भी 6 गिद्द पाया जाना सुखद है, क्योंकि यह एक तरह से पर्यावरण के सफाई दूत के रूप में कार्य करते है।

पहाड़ी क्षेत्र कम होना भी बड़ा कारण- बताया जाता है कि 2016 में हुए सर्वे के दौरान बैतूल जिले के उत्तर वन मंडल अंतर्गत दो इजिपसियन वल्चर पाए गए थे। दक्षिण वन मंडल के डीएफओ के मुताबिक इस इलाके में पहाड़ी क्षेत्र कम होने, घोंसले बनाने के लिए स्थानों की कमी होने, ब्रीडिंग की संभावनाओं के कम होने के कारण गिद्धों का न पाया जाना सामने आया है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग ने गिद्ध की गणना की थी। वनकर्मियों ने अपने-अपने वन परिक्षेत्र के जंगलों में गिद्ध की तलाश की। जिसमें 6 गिद्द मिले। यहां गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। इस साल 2026 में प्रदेश स्तर पर की गई गिद्ध गणना में यहां लगभग 15 हजार से अधिक विभिन्न प्रजाति के गिद्ध पाए गए है।

तीनों वन मंडल की हर बीट में हुआ सर्वे

गिद्धों की गणना साल में दो बार की जाती है। पहली गणना फरवरी यानि शीत ऋतु में होती है, वहीं दूसरी गणना ग्रीष्मकालीन की जाती है। इस दौरान स्थानीय और प्रवासी गिद्धों की गणना आसानी से हो जाती है। इस बार वन कर्मियों ने जिले की बैतूल वन वृत्त के अंतर्गत 443 बीटो में तीन दिन तक यह सर्वे किया। जिसमें सभी बीटो के वनरक्षक शामिल रहे। उन्होंने हर वन क्षेत्र की बीट के अलावा गौशालाओं के आसपास, मांस कटाई क्षेत्रों, कसाई के स्थलों के पास गिद्धों की गणना की। इसमें वन के अलावा राजस्व क्षेत्र भी शामिल था। गिद्द गणना के नोडल अधिकारी श्री आवसे ने बताया कि गिद्ध जैसे पक्षी पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं और ये ईको सिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। ये मृत जानवरों के शरीर को चट कर, पर्यावरण में संतुलन बनाये रखते हैं और मिट्टी में खनिजों की वापसी की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मृत शवों को समाप्त कर वे संक्रामक बीमारियों को फैलने से भी रोकते हैं।

गिद्धों के संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है

(1) गिद्धों के घोंसले की पहचान करके उनका संरक्षण करना।

(2) गिद्धों के महत्व और उनकी घटती आबादी से होने वाले विपरीत परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना।

(3) गिद्ध पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। गिद्ध जैसे पक्षी पर्यावरण के प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं, जो मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते है।

इनका कहना है-

22 से 24 मई तक तीन दिन गिद्धों की गणना के लिए जिले में सर्वे हुआ था। इस दौरान तीन प्रजाति के 6 गिद्दे मिले है। वैसे बैतूल जिले में पहाड़ी क्षेत्र कम और जंगल एरिया ज्यादा होने से भी गिद्ध नहीं आते है।

– **अरिहंत कोचर,** डीएफओ, दक्षिण वन मंडल

बैतूल कांग्रेस को मिला नया संगठनात्मक बल, 36 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की सूची जारी

बैतूल। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश नेतृत्व की सहमति से जिले के 36 प्रकोष्ठों और विभिन्न समाज समन्वय इकाइयों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस संगठन विस्तार को कांग्रेस की आगामी राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी कवायद माना जा रहा है। पार्टी ने हर वर्ग और समुदाय को प्रतिनिधित्व देकर जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने का संदेश दिया है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि संगठन प्रभारी महासचिव डॉ. संजय कामले एवं उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी सुखदेव पांसे की सहमति से जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके तहत जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक, श्रमिक, व्यापारिक, शैक्षणिक और जनजातीय वर्गों को साधने की रणनीति के तहत अलग-अलग प्रकोष्ठों में जिम्मेदारियां सौंपी हैं। प्रभारी समस्त प्रकोष्ठ एवं विभाग डॉ महेंद्र सिंह चौहान द्वारा जारी सूची में सद्भावना एवं कौमी एकता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सफी पारेख को दी गई है, जबकि विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोहर नायक को बनाया गया है। फुटकर एवं लघु व्यावसायिक समाज प्रकोष्ठ की कमान नीरज कटारिया, सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी राहुल छत्रपाल तथा सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ का नेतृत्व ललित गोयर को सौंपा गया है। धर्म एवं मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ में पं. प्रवीण जोशी, मसीह समाज समन्वय समिति में स्पेंसर लाल और केश कला शिल्पी प्रकोष्ठ में राजेश सराठे को नियुक्त किया गया है। महिला उत्पीडन् निवारण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सीमा अतुलकर को दी गई है। परिवहन प्रकोष्ठ में हेमंत (मन्नू) देशमुख, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में रूपेश आर्य और दिव्यांग प्रकोष्ठ में रामकिशोर कसरादे बडोरा को दायित्व सौंपा गया है।

कलेक्टर से मिलने पर अड़े एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा

पुलिस को धक्का देकर कलेक्ट्रेट में घुसे छात्र, फीस और छात्रावास मुद्दों पर प्रदर्शन

बैतूल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों और छात्र नेताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन, कलेक्टर को ही सौंपने की मांग पर अड़े कार्यकर्ताओं ने पहले पोर्च में धरना दिया, फिर मुख्य गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों को धक्का देकर अंदर घुस गए और कलेक्टर चैंबर के पास पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही। धक्का-मुक्की के दौरान दो पुलिसकर्मी भी दरवाजे के पास गिर पड़े। परिषद के कार्यकर्ता विभिन्न छात्र समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। प्रशासन की ओर से एडीएम वंदना जाट, एसडीएम अभिजीत सिंह और तहसीलदार पूनम साहू को ज्ञापन लेने भेजा गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। छात्र नेताओं का कहना था कि वे अपनी मांगें सीधे कलेक्टर के सामने ही रखेंगे। काफी देर तक कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट की ओर बढना शुरू कर दिया। इस दौरान गेट पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों को धक्का देते हुए अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र नेता कलेक्टर चैंबर के बाहर पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी मौके पर पहुंचे तथा कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर बैतूल में नहीं होने के कारण मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफी देर तक चली समझाइश और बातचीत के बाद कार्यकर्ता शांत हुए। अंत में उन्होंने एडीएम वंदना जाट को ज्ञापन सौंपा।

प्राइवेट स्कूलों की फीस निर्धारित करने की मांग..

ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद ने निजी स्कूलों की फीस सरकारी मानकों के अनुसार निर्धारित करने, विद्यार्थियों को एक ही दुकान से किताबें खरीदने के दबाव पर रोक लगाने, स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करने तथा छात्रावासों में सीटें बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा छात्रावासों में साफ-सफाई और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, शासकीय महाविद्यालयों में एमएससी, एमकॉम और एमए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में जिला संयोजक देवेन्द्र पांसे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मयंक घोरले, नगर मंत्री साहिल शेख, प्रांत जनजाति छात्र कार्य प्रमुख मानिक कुमरे, रवि तायवाडे, शुभम सेन, भीमपुर नगर मंत्री सोनू विश्वकर्मा एवं जिले के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में विश्व के विभिन्न देशों के शोधकर्ता, शिक्षाविद्, विशेषज्ञ और छात्र शामिल हुए

धार। इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस (-2026) का सफल समापन काठमांडू नेपाल में हुआ। वर्ल्ड रिसर्च कॉन्फ्रेंस एवं ऑर्किड इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा नेपाल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के शोधकर्ता, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और छात्र शामिल हुए।

वर्ल्ड रिसर्च कॉन्फ्रेंस के समन्वय में सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सतत विकास जैसे विविध विषयों पर कुल 117 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इनमें से कई पत्र भौतिक रूप से और कुछ ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत हुए। वर्ल्ड रिसर्च कॉन्फ्रेंस के सीईओ राजेश वर्मा ने बताया कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस विभिन्न देशों में समय-समय पर आयोजित होती रहती हैं। इससे शोधकर्ताओं को वैश्विक मंच मिलता है और ज्ञान के आदान-प्रदान से सभी को लाभ होता है।

उद्घाटन सत्र में डॉ. बिजय लाल प्रधान ने स्वागत भाषण दिया। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति बिजु कुमार थपलिया ने कहा कि शोध का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

तकनीकी सत्रों में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के मुख्य व्याख्यान, शोध पत्र प्रस्तुति और संवाद सत्र हुए, जिनमें वैश्विक शोध प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने कहा कि इस मंच से ज्ञान के आदान-प्रदान, पेशेवर सहयोग और भविष्य की शोध साझेदारी के महत्वपूर्ण अवसर मिले।

वर्ल्ड रिसर्च कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर डॉ. राकेश उपाध्याय ने आयोजकों, प्रतिभागियों और सहयोगी संस्थानों का आभार माना- समापन पर वर्ल्ड रिसर्च कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर डॉ. राकेश उपाध्याय ने सभी आयोजकों, प्रतिभागियों और सहयोगी संस्थानों का आभार माना। उन्होंने कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय मंच नवाचार और अंतःविषय सहयोग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सम्मेलन ने नवाचार, अंतःविषय सहयोग और अकादमिक नेटवर्किंग के लिए एक सशक्त अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया।

साहित्य साधना के लिए साहित्यकार देवेंद्रसिंह सिसौदिया 'प्रेरणा सम्मान' से सम्मानित

सम्मान सिसौदिया को उनकी चर्चित कृति 'शुभ मुहूर्त' के लिए प्रदान किया गया

धार। कलामोहन भाषा, साहित्य एवं संगीत केंद्र, सुखेड़ा द्वारा आयोजित वार्षिक प्रेरणा सम्मान समारोह 2026 में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु धार निवासी साहित्यकार देवेंद्रसिंह सिसौदिया को 'प्रेरणा सम्मान' से अलंकृत किया गया। यह सम्मान उनकी चर्चित कृति 'शुभ मुहूर्त' पर प्रदान किया गया।

समारोह में स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज (भूटान), डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा (कुलानुशासक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन), पुरातत्वविद् डॉ. आर. सी. ठाकुर (महिदपुर), लोक संस्कृति संवाहिका श्रीमती भारती सोनी (झाबुआ) एवं संस्था निदेशक डॉ. कारुलाल जमड़ा 'कारुण्य' के करकमलों द्वारा श्री सिसौदिया को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

जनसमस्याओं के निराकरण हेतु देर शाम तक चलता रहा जनसंवाद कार्यक्रम

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की जनसुनवाई में उमड़ी भारी भीड़

धार। धार-महू लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद एवं भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज जिला भाजपा कार्यालय एवं सांसद कार्यालय में व्यापक जनसुनवाई एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया।

जनसुनवाई में लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं आमजन अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसी उद्देश्य के साथ यह जनसुनवाई आयोजित की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, हर घर जल अभियान एवं गरीब कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए मंत्री निरंतर क्षेत्रवासियों से संवाद करती रही हैं।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित

जनहितैषी योजनाओं एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर भी मंत्री महोदय ने कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य सहायता, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति एवं गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। आज की जनसुनवाई में विशेष रूप से स्वास्थ्य सहायता, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान सहायता, सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, अवैध अतिक्रमण, पुलिस सहायता, राजस्व प्रकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। धरमपुरी, मनावर, सरदारपुर, बदनावर, गंधवानी, कुक्षी एवं महू सहित लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। जनसुनवाई का निर्धारित समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक था, किन्तु क्षेत्रवासियों की भारी उपस्थिति के कारण यह कार्यक्रम लगातार शाम 7 बजे तक चलता रहा। इस दौरान श्रीमती ठाकुर ने कई मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर तत्काल निराकरण करवाया तथा शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि जनता की सेवा ही उनका सर्वोच्च दायित्व है तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया कि वे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मूंग की खरीदी पंजीयन ,तवा बैकवाटर में जमी सिल्ट हटाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। पूर्व जनपद पंचायत सदस्य एवं सोमनाथ आदिवासी संगठन के राजकुमार रघुवंशी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी को मूंग की खरीदी हेतु पंजीयन तथा तवा बैकवाटर राईट बैंक केनाल (नहर) में जमी सिल्ट की हटाने के संबंध में राज्यपाल को संबोधित करते ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र के सभी कृषकगणों ने गर्मी के सीजन में मूंग की फसल की बोवनी की है। लेकिन अभी तक मूंग खरीदी देतु पंजीयन नहीं किया जा रहा है। पंजीयन नहीं होने के कारण मूंग की फसल बिक्री के स्लॉट भी बुक नहीं हो रहें हैं। किसानों को मूंग धान की फसल की बोवनी भी तैयारी भी करना है। पंजीयन नहीं होने के कारण किमान इधर उधर भटक रहे है ।

नाम परिवर्तन की सूचना

हम, विष्णु सेन एवं कृष्णा बाई, निवासी ग्राम सियाखेड़ी, जाफराबाद, सीहोर, म.प्र. - 466114, अपने नाबालिग पुत्र **'यश सेन'** (जन्म तिथि 02/12/2012) का नाम शपथ पत्र द्वारा बदलकर **'आयुष सेन'** रखते हैं। भविष्य में वह **'आयुष सेन'** नाम से जाना जाएगा। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

विष्णु सेन एवं कृष्णा बाई

समय-सीमा में निराकरण नहीं करने और गलत जानकारी देने वालों पर होगी पैनाल्टी

लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अभियानों की प्रगति परखी

विदिशा , निप्र। विदिशा कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण अभियानों एवं लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद आवेदन लंबित रखने तथा समीक्षा बैठकों में त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर पैनाल्टी की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। विशेष रूप से 500 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा ऐसे मामलों की शनिवार को पुनः विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं संतोषजनक समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।

बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएम मॉनिटरिंग, केंद्रीय मंत्री, प्रभारी मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी जानकारी ली गई। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से लंबित प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ

कार्य करने के निर्देश दिए। ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल निगम के अधिकारियों ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न होने पाए तथा शिकायत मिलने पर तत्काल निराकरण किया जाए। बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों में नवीन प्रवेश, पाठ्यपुस्तकों के वितरण, साइकिल वितरण तथा छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्रस्तुत की गई। साथ ही आईटीआई की विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश प्रक्रिया की प्रगति से भी अवगत कराया गया।

निर्माण कार्य कराने वाले विभागों की समीक्षा के दौरान मजदूरी पर कार्यरत श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि श्रमिकों को शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक में संदीपनी हाई स्कूल के नव-निर्मित भवनों में शिफ्ट होने के उपरांत रिक्त हुए पुराने भवनों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि रिक्त भवनों का उपयोग अन्य शासकीय विभागों के कार्यों हेतु किया जाए ताकि शासकीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। इसके लिए निरीक्षण प्रपत्र का प्रारूप तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, श्रम सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं अभियानों की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोडिया, एसडीएम क्षितिज शर्मा, संयुक्त कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं खंड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

वन भूमि से 5 हेक्टेयर अतिक्रमण हटाया

विदिशा , निप्र। लटेरी वन विभाग द्वारा अवैध कटाई एवं अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वन मंडल अधिकारी श्री हेमंत यादव के निर्देशन में दक्षिण लटेरी रेंज के बीट मुस्करा अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी-300 में दिनांक 27 मई 2026 को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। इस संबंध में वन अपराध हिम्मत सिंह यादव एवं पहलवान सिंह यादव के नाम से पंजीबद्ध किया गया था। वन विभाग की टीम ने पोकलेन एवं जेसीबी मशीनों की सहायता से अतिक्रमण को हटाते हुए भूमि को गड्ढे कर बेदखल किया। साथ ही भविष्य में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए भूमि पर कटीली प्रजातियों के बीज भी डाले गए। बताया गया कि उक्त वन भूमि पर कई वर्षों से भूमाफियाओं का कब्जा था तथा अन्य साथियों के साथ मिलकर लगातार अतिक्रमण का दायरा बढ़ाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग एवं पुलिस बल की मौजूदगी के कारण अतिक्रमणकारी विरोध नहीं कर सके। यह पूरी कार्रवाई परिक्षेत्र अधिकारी विवेक चैधरी के नेतृत्व में संपन्न हुई। मौके पर लटेरी उत्तर एवं दक्षिण रेंज का समस्त वन अमला उपस्थित रहा। साथ ही थाना शमशाबाद एवं थाना लटेरी का पुलिस बल भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं अतिक्रमण की रोकथाम हेतु जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा ऐसे मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

युवाओं और खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकालकर दिया जल संरक्षण का संदेश

बैतूल (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेशव्यापी 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत गंगा दशमी पर्व के पावन उपलक्ष्य में जिला बैतूल में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से युवाओं और खिलाड़ियों ने आमजन को जल स्त्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन के प्रति जागरूक किया। यह गरिमामय आयोजन अपर कलेक्टर, बैतूल श्रीमती वंदना जाट के कुशल निर्देशन एवं जिला खेल अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील के नेतृत्व में स्थानीय मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर शहर के मुख्य मार्गों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल ही जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल स्त्रोतों को सहेजना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। खिलाड़ियों और युवाओं का यह कारवां मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों और मार्गों से गुजरा, जहाँ गगनभेदी नारों और संदेशों के माध्यम से नागरिकों को जल गंगा संवर्धन अभियान से जुड़ने की अपील की गई।

आदतन अपराधियों को प्रति सप्ताह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में आरोपी बनवारी रायसिक पिता मंगू सिंह रायसिक निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़ी जिला रायसेन को तत्काल प्रभाव से आगामी 06 माह की अवधि तक प्रत्येक सप्ताह के दिन सोमवार को तहसीलदार तहसील बाड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित थाना प्रभारी अनावेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे। उल्लेखनीय है कि आरोपी बनवारी रायसिक वर्ष 1997 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में 31 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी गोलू अहिरवार पिता रतिराम अहिरवार निवासी ग्राम बेरखेड़ी बरामद गढ़ी थाना बेगमगंज जिला रायसेन को तत्काल प्रभाव से आगामी 06 माह की अवधि तक प्रत्येक सप्ताह के दिन गुरूवार को तहसीलदार तहसील बेगमगंज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य शिविर में 745 मरीजों का किया उपचार

बैतूल (निप्र)। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जिले में 20 स्वास्थ्य शिविर लगाने की प्राप्त स्वीकृति के परिपालन में सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मासोद में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनाली विनोद इरपाची, विधायक प्रतिनिधि श्री राजेश पाठक, सरपंच श्रीमती संगीता धोटे, श्री विजय घोड़की, श्री रवि ठाकुर जनपद पंचायत सदस्य श्री उमेश बामने द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि शिविर में 418 पुरुष एवं 327 महिला कुल 745 मरीजों का पंजीयन कर जांच एवं उपचार किया गया।

राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण, हितग्राहियों को मिल रही राहत

नर्मदापुरम , निप्र। नर्मदापुरम कलेक्टर के सतत दिशा-निर्देशों का असर तहसील माखननगर में देखने को मिल रहा है। यहां राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निपटारे में तेजी आई है। इस वर्ष अब तक नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के 437 प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने राजस्व मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए न्यायिक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के कार्यों को अलग कर दिया है। इसी क्रम में माखननगर में पूर्णकालिक न्यायिक तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की पदस्थापना की गई है। तहसीलदार महेन्द्र चौहान एवं नायब तहसीलदार सुनील गढ़वाल के पदस्थ होने के बाद राजस्व न्यायालय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित हो रहा है। सभी प्रकरणों की सुनवाई विधि अनुसार की जा रही है। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा भी माखननगर क्षेत्र के प्रकरणों की सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को तहसील माखननगर में ही की जा रही है। इससे हितग्राहियों को मुख्यालय नर्मदापुरम के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे और उनका काम स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं प्रोटोकॉल ड्यूटी जैसे गैर न्यायिक कार्यों के लिए नायब तहसीलदार सुश्री श्रद्धा गोस्वामी को पदस्थ किया गया है। इससे न्यायिक

अधिकारी अपना पूरा समय राजस्व प्रकरणों पर दे पा रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण से राहत मिलने पर आमजनों एवं अधिवक्ताओं ने कलेक्टर का आभार व्यक्त किया है।

जिलों में उद्योगों एवं फूड प्रोसेसिंग को प्राथमिकता से बढ़ावा मिले

इसके लिए कलेक्टर्स सभी हर संभव प्रयास करें : मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन

नर्मदापुरम , निप्र। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने जिले में विभिन्न उद्योगों एवं फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हुए बैंक फाइनेंस की सुविधा का विस्तार करते हुए उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें एवं फूड प्रोसेसिंग तथा उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली पानी एवं सड़क की सुविधा उपलब्ध कराए। उद्योगों एवं फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने से जिले की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ करेगी। उन्होंने एक जिला एक उत्पादन पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश देते हुए कहां की सभी जिले अपने उत्पादनों कि जीआईएस ट्रैकिंग अनिवार्य रूप से करें साथ ही जिले के प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हुए प्रोडक्ट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए उत्पादनो की पैकेजिंग पर भी विशेष रूप से कार्य करें, मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को प्रेरित किया जाए कि वे

यदि गेहूं की बजाय गेहूं के मैदा या आटा बनाकर विक्रय करे तो किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की जो जमीन उद्योग धंधों के लिए दी गई है उस जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो, साथ ही उन्होंने निर्देश दिए की उद्योगो की स्थापना के लिए यदि शासकीय भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो प्राथमिकता से शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है की मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन बुधवार को प्रदेश के सभी संभाग के संभाग आयुक्त एवं समस्त जिलों के कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की अदयतन प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव श्री जैन ने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह जनजातीय वर्ग को शासन की टंट्या मामा योजना एवं बिरसा मुंडा योजना का लाभ दिलाने के लिए सतत संपर्क कर उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाते हुए लक्ष्य में शत प्रतिशत प्रगति लाए। भीषण गर्मी को मद्देनजर रखते हुए मुख्य सचिव में सभी कलेक्टर को निर्देश दिए की वह अपने अपने जिले में पेयजल आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें, कहीं भी पेयजल को लेकर अप्रिय स्थिति निर्मित न होने पाए। उन्होंने पेयजल की उपलब्धता की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी माह में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए गेहूं एवं अन्य उपज को सुरक्षित रखने हेतु वेयरहाउस एवं मंडियो में तिरपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करें, संभावित बाढ एवं बारिश से निपटने के लिए एवं आम जनों को राहत देने के लिए शिविर, आवश्यक औषधीय एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही सभी कलेक्टर्स प्रतिदिन गेहूं खरीदी परिवहन एवं भंडारण तथा कृषकों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करें। इस दौरान उन्होंने अवैध खनिज के उत्खनन परिवहन और भंडारण पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन से बदली ग्रामीण जीवन की तस्वीरपथरई

परसवाड़ा, सुपलई भाग-4 एवं अटाश्री में उत्सवपूर्वक हुआ नल जल योजनाओं का हस्तांतरण

नर्मदापुरम , निप्र। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शासन द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत नल जल योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जिले में लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रारंभ हुए इस महत्वाकांक्षी अभियान में नर्मदापुरम जिला, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एक सशक्त सहभागी के रूप में उभर रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की सतत मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन में जिले में योजनाओं का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है तथा योजनाओं के हस्तांतरण को ग्रामवासी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी उत्सव का उदाहरण बने जिले के ग्राम पथरई, परसवाड़ा, सुपलई भाग 4 एवं ग्राम अटाश्री जहां अब ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए किसी भी प्रकार की मेहनत तथा कड़ा परिश्रम ना करते हुए घर पहुंची नल जल योजना से शुद्ध एवं साफ पेयजल मिल सकेगा। नल जल योजना ग्रामीणजनों के लिए वरदान साबित हुई और पीने के पानी को लेकर वे आत्मनिर्भर होकर अब सुकुन की जिन्दगी जीने लगे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से पानी लाने की समस्या से निजात मिल गई है जिससे अब समय की भी बचत होने लगी है। इस बचे हुए समय का सदुपयोग अब ग्रामीण अपने सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे जिसमें स्वरोजगार की तरफ भी ग्राम वासियों ने अपने कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत पथरई की तीनों योजनाएं पथरई, परसवाड़ा एवं सुपलई भाग 4 का हस्तांतरण उत्सव पूर्वक संपन्न किया गया। इस उपलक्ष्य में तीनों ग्रामों में कलश यात्रा निकाली गई और लोक गीतों का गायन किया गया। इसी प्रकार जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत उटिया शंकर के ग्राम अटाश्री में भी नल जल योजना का हस्तांतरण उत्सव पूर्वक संपन्न किया गया। इस दौरान ग्राम में कलश यात्रा निकाली गई। लोकगीतों का गायन किया गया। उत्सव के दौरान लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री, उपयंत्री ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने उपखंड सोहागपुर में ग्राम पथरी में 25.99 लाख रुपयों की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना बनाई जिसके तहत लगभग 252 घरों में नल कनेक्शन देकर लोगों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार ग्राम परसवाड़ा, सुपलाई भाग-4 सम्मिलित मजरा नया काजरी, एवं साकई एवं अटाश्री में 81.98 लाख रुपयों की लागत से एक नई योजना बनाई जिसके तहत लगभग 278 घरों में नल कनेक्शन देकर लोगों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई। पेयजल सुविधा विस्तार के साथ ही अब ग्रामवासियों को नल से शुद्ध जल मिल रहा है।

ग्राम शिवपुर की नल-जल योजना का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

नर्मदापुरम , निप्र। विकासखंड सिवनी मालवा के ग्राम पंचायत शिवपुर अंतर्गत ग्राम शिवपुर की नल-जल योजना का निरीक्षण नायब तहसीलदार श्री पूनमसिंह सलामे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं सहायक यंत्री भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान संबंधित ठेकेदार एवं निवेदक को योजना के शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा गया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत को योजना के नियमित संचालन एवं संधारण के लिए एक नवीन ऑपरेटर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि ग्राम के सभी नागरिकों को निरंतर एवं सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो सके। उल्लेखनीय है कि उक्त नल-जल योजना अंतर्गत ग्राम शिवपुर में 375 किलोलीटर क्षमता की उच्च स्तरीय पानी की टंकी निर्मित की गई है। योजना के तहत तीन सफल नलकूपों से पानी एकत्रित कर टंकी के माध्यम से पूरे ग्राम में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।

मुख्य सचिव श्री जैन ने कलेक्टर कांफ्रेंस में की समीक्षा

हर जिला अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की पहल करे

- आमजन के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश
- अवैध गतिविधियों और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें
- सीहोर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से वीसी में शामिल हुए कलेक्टर-एसपी सहित संबंधित अधिकारी

सीहोर , निप्र। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में संवेदनशील प्रयास करे। लोक सेवा गारंटी, सी.एम. हेल्पलाइन और जनसुनवाई राज्य शासन के सुशासन के पैमाने हैं। सभी अधिकारियों को आमजन से जुड़े मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। उन्होंने अवैध गतिविधियों को सख्ती से रोकने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री जैन ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक के साथ योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीहोर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर श्री बालागुरू के., एसपी श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव और जिला वन मंडल अधिकारी श्रीमती अर्चना पटेल सहित संबंधित अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री जैन ने सुशासन के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की और कलेक्टर्स से कहा कि नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण हो और प्रयास करें कि एक भी प्रकरण निर्धारित अवधि से बाहर नहीं जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान अधिकारी मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लें तथा शिकायत का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। उन्होंने स्वामित्व योजना में और बेहतर कार्य करने की जरूरत बताई तथा राजस्व संग्रहण बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने नजूल नवीनीकरण के कार्य को जन-अभियान चलाकर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सी.एम हेल्पलाइन के शत-प्रतिशत प्रकरणों को अटेंड करने और पेयजल की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करने को कहा है।

राइट क्लिक

हिंदी पत्रकारिता: 'मार्तंड' के 'उदंत' की मूल तासीर अक्षुण्ण रहेगी !

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं। संपर्क- 9893699939 ajaybokil@gmail.com

हिंदी भाषियों के अज्ञान के अंधेरे को दूर कर उन्हें जागृत, शिक्षित और संसूचित करने के उद्देश्य से आज से ठीक दो सौ साल पहले कलकत्ता से निकले पहले हिंदी अखबार 'उदंत मार्तंड' के मर्म का प्रकाश अब बहुत दूर तक फैल चुका है। हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम इस 'समाचार सूर्य' के प्रकाशन की दूसरी शताब्दी के साक्षी हैं, वरना इस पत्र की पहली शताब्दी के वक्त हिंदी भाषियों को ज्ञान ही नहीं था कि हिंदी पत्रकारिता का प्रथम सूरज 30 मई 1826 को चमका था और पं. युगल किशोर शुक्ल के संपादन में अपनी चमक बिखेर कर डेढ़ साल बाद बंद भी हो गया। अलबत्ता शुक्लजी ने हिंदी पत्रकारिता का बीजारोपण कर दिया था, जो आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा है, विस्तारित होता जा रहा है। यह आधुनिक भारत आरंभ भी था। हिंदी पत्रकारिता की आत्मा को शुक्लजी ने अपने अखबार में सर्वप्रथम 'हिंदुस्तानियों के हित के हेत' के रूप में रेखांकित कर दिया था। यही उसका धर्म है, यही मर्म और यही प्रतिबद्धता है। हिंदी पत्रकारिता की पहचान उसके जनता से जुड़े रहने में निहित है। हालांकि कुछ लोगों की नजर में हिंदी पत्रकारिता प्रतिरोध की पत्रकारिता है और उसे अपना यह चरित्र कायम रखना चाहिए। सत्ता का भोंपू बनना उसकी प्रकृति और नीयत नहीं है। कुछ लोग कालखंड और चरित्र के हिसाब से हिंदी पत्रकारिता को मिशन, कमीशन और एजेंडा पत्रकारिता में बांटते हैं। बीते एक दशक में हिंदी पत्रकारिता को 'हिंदू पत्रकारिता' अथवा 'गोदी मीडिया' कहकर उसकी आलोचना की गई। लेकिन अपनी तमाम कमियों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता आज अपने इतिहास के सबसे प्रभावशाली दौर में अगर आ खड़ी है तो इसका श्रेय आदि पत्रकार युगलकिशोर शुक्ल को ही जाता है, जिन्होंने तब शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो एक नए इतिहास की नींव रख गए हैं। वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता का विराट रूप आज अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजीटल मीडिया और रेडियो मीडिया के जरिए बना है। यह बात अलग है कि इसका इस्तेमाल मीडिया मालिक, सत्ता, कई पत्रकार और इंफ्लूएंसर्स अपने-अपने ढंग से कर रहे हैं।

दो साल किसी भी विधा के परिपक्व होने तथा परंपरा और विरासत में तब्दील होने के साक्षी होते हैं। इस दौरान हिंदी पत्रकारिता ने कई उतार-चढ़ाव देखे। अनेक चुनौतियों का सामना किया और अब नई चुनौतियों से जूझ रही है। दरअसल हिंदी पत्रकारिता भारत के आधुनिक और विकसित राष्ट्र में रूपांतरित होते जाने के की साक्षी भी है। इसने अंग्रेजों से लोहा लिया, स्वतंत्रता संग्राम में योद्धा की भूमिका निभाई। आजादी के पश्चात लोकतंत्र को बचाने के लिए चौथे खम्भे के किरदार में रही। आज सूचनाओं के कोलाहल और सोशल मीडिया के अराजक माहौल में भी पारंपरिक हिंदी पत्रकारिता अपनी पहचान बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है।

हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी के पहले अखबार 'उदंत मार्तंड' का पहला शताब्दी वर्ष संभवतः अनसुना ही निकल गया। जाने-माने पत्रकार और सप्रे संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर के अनुसार जनवरी 1931 तक यह माना जाता रहा कि हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 1 जनवरी 1845 में काशी से प्रकाशित होने वाले 'बनारस अखबार'से हुई। 'मार्डन रिव्यू' के सहायक संपादक ब्रजेन्द्र नाथ बंद्योपाध्यारय (बनर्जी) जब भारतीय भाषाओं की पत्रकार-कला का इतिहास लिख रहे थे, तब उनकी शोध दृष्टि में 'उदंत मार्त्तण्ड 'की फाइल आई। यह तथ्य सामने आया कि हिन्दी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्त्तंड' है। यानी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास एक झटके में 19 साल पीछे चला गया। संयोग से यह घटनाक्रम भी हिंदी पत्रकारिता के समावेशी चरित्र का ही सूचक है कि हिंदी के पहले अखबार की खोज एक बंगाली भाषी विद्वान ने की तो 'उदंत मार्तंड' के उजागर होने से पहले जिस 'बनारस अखबार' को हिंदी का आद्य अखबार समझा जाता रहा, उसके संपादक एक मराठीभाषी गोविंद रघुनाथ थत्ते थे।

बीते दो सौ सालों में हिंदी पत्रकारिता ने समय के साथ अपना रूप रंग, तेवर और धार बदली है। लेकिन आज हिंदी पत्रकारिता की प्रामाणिकता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं बावजूद इसके कि पत्रकारिता कभी भी समय, परिस्थिति और समाज निरपेक्ष नहीं हो सकती। आरोप यह भी है कि राष्ट्रवादी सोच और पत्रकारीय मूल्यों के बीच की लक्ष्मण रेखा धुंधली होती जा रही है। हालांकि इसके पीछे कारण जनता की सोच में परिवर्तन और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तकाजे भी हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कई बार लगता है कि पत्रकारिता का भौकाल एजेंडे में परिवर्तित हो चुकी है, जिसमें सत्य का पता लगाना कठिनतर होता जा रहा है। सूचनाएं अपनी पवित्रता और प्रामाणिकता खोकर फेक और दुष्प्रचार की खबरों में तब्दील होती जा रही हैं। इसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। उसकी व्याप्ति पारंपरिक मीडिया से भी ज्यादा हो जाने के कारण लोगों का इसी फेक समाचार जगत को असली समझ बैठना, एक स्वतंत्र देश, स्वस्थ समाज और मानवीय सरोकारों के लिए भी घातक है।

निस्संदेह हिंदी पत्रकारिता का जन्म टीआरपी या लाइक्स बटोरने के लालच के बजाए अपने पाठकों तक सम सामयिक घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचनाएं पहुंचाने और सद्विचारों से अवगत कराने के सात्विक आग्रह से हुआ है। अब 'भारत और भारतीयों के हित के हेत' में कई नए कारक और स्वार्थ जुड़ गए हैं।

शुक्लजी ने हिंदी पत्रकारिता की नींव जिस दौर में रखी थी, तब संसाधनों और सूचना स्रोतों का बेहद टोटा था। कलकत्ता से बाहर अखबार के वितरण का जरिया भी केवल डाक ही था। इसके लिए भी तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जो तब इसे 'कंपनी मेल' कहती थी। तब न तो फोन थे, न रेडियो था और न ही कम्प्यूटर, रेलवे भी तब तक भारत में चालू नहीं हुई थी। तार सेवा भी नहीं थी। छपाई की मशीन को छोड़ दें तो सारा काम मानवचलित ही था। उस दौर में भी शुक्लजी ने हिम्मत कर डेढ़ साल तक निकाला। अखबार की लेखनी धारदार और व्यवस्था व दमन विरोधी थी, इसलिए उस पर अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़नी ही थी। उन्होंने समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दीं। अंततः अखबार बंद करना पड़ा। लेकिन शुक्लजी के साथ था हौसला, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। हिंदी पत्रकारिता का जन्म इसी पालने में हुआ है। शुक्लजी भी भारतीयों के हितों की प्रतिकूल घटनाओं पर प्रखर और तथ्यात्मक टिप्पणी करते थे, आज भी उसकी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। लोकोन्मुखी और लोकतांत्रिक संघर्ष ने ही हिंदी पत्रकारिता के मूल्य गढ़े हैं।

हिंदी पत्रकारिता के दो सौ साल तमाम तरह की चुनौतियों से मुकाबिल होने के भी रहे हैं। अब नए जमाने में चुनौतियां भी नई हैं। मसलन डिजीटल माध्यमों से होने वाली गलत सूचनाओं की बौछार और एक खास पक्ष में झुकी पत्रकारिता। सत्ता और कारपोरेट दबाव के आगे नतमस्तक न होने, किसी एजेंडे का हिस्सा न बनने तथा वित्तीय संकट से जूझना भी शामिल है। आज संतुलित, तथ्यात्मक और तार्किक रिपोर्टिंग दूभर होती जा रही है। हर बात को सनसनीखेज बनाने के चलन और बाजार के दबाव ने विश्वसनीय और सत्यान्वेषी पत्रकारिता को पीछे धकेल दिया है। निर्भीक अभिव्यक्ति को आलोचना के आईने में देखा जाने लगा है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता के लिए यह कोई नई बात नहीं है। शुक्लजी ने भी जब 'उदंत मार्तण्ड' शुरू किया था, वो समय देश में राजनीतिक अराजकता, आपसी संघर्ष, अशिक्षा और देश को गुलाम बनाने वाली उपनिवेशवादी ताकतों के कसते शिकंजे का था। तब भी देशभक्त ताकतें अपने विवेक और संसाधनों के साथ जूझ रही थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। लेकिन 'हिंदुस्तानियों के हितों' का तकाजा कमोबेश वही है, फर्क इतना है कि उसका स्वरूप बदल गया है।

हमारे लिए गर्व की बात यह है कि आज हिंदी पत्रकारिता अपने भीतर दो सौ वर्षों का अनुभव, ज्ञान, संघर्ष, अपने मूल्य और प्रतिबद्धताएं समेटे हुए है। यही पूंजी और जज्बा हमे भावी चुनौतियों से जूझने में मदद करेगा। जिम्मेदारी उन सच्चे पत्रकारों की भी है कि शुक्लजी की भावना के अनुरूप हिंदी पत्रकारिता के मूल्य कैसे अबाधित रहें। हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप, कार्यशैली भले बदले, किंतु उसकी अंतरात्मा न बदले। जब तक हिंदी पत्रकारिता जनता से जुड़ी रहेगी, तब इस समाचार के इस सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। कुछ लोग भले इसे अति आत्मविश्वास मानें, लेकिन 'मार्तण्ड' के 'उदंत' की मूल तासीर यही है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का हो रहा है अधोसंरचात्मक विकास: मुख्यमंत्री

3,540 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा हाई-स्पीड कॉरिडोर मध्य भारत में कनेक्टिविटी का नया मानक स्थापित करेगा

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में विकसित हो रहे आधुनिक अधोसंरचना नेटवर्क ने भारत की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे, आर्थिक कॉरिडोर और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश को नई ऊर्जा मिल रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में विकसित की जा रही जबलपुर आउटर रिंग रोड परियोजना महाकौशल क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिखने जा रही है। प्रदेश में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग 3,540 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही 114 किलोमीटर लंबी यह महत्वाकांक्षी परियोजना जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी,

व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया कि जबलपुर क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने वाली यह परियोजना शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के साथ-साथ क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों को भी मजबूती प्रदान करेगी। फोर लेन वाले इस अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण विशेष रूप से शहर के बाहर से आने-जाने वाले भारी एवं लंबी दूरी के यातायात को सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

शहर को मिलेगी ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत

विगत वर्षों में जबलपुर में तेजी से हुए शहरी विस्तार, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि तथा यात्री एवं मालवाहक वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात दबाव लगातार बढ़ा है। शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम, लंबा यात्रा समय और ईंधन की अतिरिक्त खपत आम समस्या बन गई थी। आउटर रिंग रोड परियोजना इन चुनौतियों का दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसके संचालन से लंबी दूरी के वाहनों का आवागमन शहर के बाहर से होगा, जिससे शहरी सड़कों पर दबाव कम होगा और आम नागरिकों को अधिक सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध होगी।

लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन को मिलेगी नई गति

जबलपुर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। आउटर रिंग रोड बनने के बाद मालवाहक वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, जिससे परिवहन लागत और समय दोनों में कमी आएगी। ईंधन की बचत होगी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अधिक कुशल बन सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भविष्य में जबलपुर को मध्य भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नर्मदा पर बनेगा आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक- परियोजना का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा नर्मदा नदी पर निर्मित किया जा रहा लगभग 750 मीटर लंबा एक्सट्राडोज्ड ब्रिज है। आधुनिक तकनीक से तैयार किया जा रहा यह पुल न केवल परिवहन सुविधा को बेहतर बनाएगा बल्कि भविष्य में क्षेत्र की एक विशिष्ट पहचान के रूप में भी स्थापित होगा। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी पर निर्मित यह पुल आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण होगा।

पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बड़ा लाभ

जबलपुर की पहचान केवल औद्योगिक और प्रशासनिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी है। भेड़ाघाट की संगमरमरी घाटियां, धुआंधार जल प्रपात, ग्वारी घाट, नर्मदा तट और निकटवर्ती कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नई रिंग रोड इन पर्यटन स्थलों तक पहुंच को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाएगी। साथ ही अमरकंटक जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक यात्रा भी पहले की तुलना में अधिक सुगम होगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

हरित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

परियोजना में पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। निर्माण कार्य में लगभग 40 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है, जो औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा पौधरोपण, हरित पट्टी विकास और आधुनिक जल निकासी व्यवस्था के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विकास, संपर्क और समृद्धि का नया अध्याय

जबलपुर आउटर रिंग रोड परियोजना केवल एक सड़क निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि महाकौशल क्षेत्र के भविष्य को आकार देने वाली विकास यात्रा है। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज आवागमन, कम ईंधन खपत, मजबूत लॉजिस्टिक्स, बढ़ते पर्यटन, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन के माध्यम से यह परियोजना क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखने जा रही है। आने वाले वर्षों में यह कॉरिडोर मध्य भारत के विकास मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करेगा।

बड़े तालाब में युवती ने छलांग लगाई

दो दोस्तों के साथ घूमने आई थी, फोन पर बात न हो पाने से तनाव में होने की आशंका

भोपाल (नप्र)। भोपाल के वीआईपी रोड स्थित बड़े तालाब में शुक्रवार सुबह एक युवती के कूदने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर नगर निगम के गोताखोर तत्काल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोर मोहम्मद इमरान, शेख आसिफ और आमिर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती को पानी से बाहर निकाला और तुरंत तलैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवती को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवती की पहचान मनीषा के रूप में हुई है, जो बैरागढ़ क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक वह पिछले कुछ समय से पारिवारिक परेशानियों से जूझ रही थी।

फोन पर बात न होने से तनाव में थी युवती- थाना प्रभारी दीपक डहरिया ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवती सुबह करीब 8 बजे अपने दो दोस्तों के साथ वीआईपी रोड पर घूमने आई थी। इसी दौरान वह किसी को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, जिससे वह तनाव में आ गई।

ट्विशा केस-सास और पति 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर

आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी, एक्ट्रेस के आखिरी घंटों का वर्चुअल रीक्रिएशन करेंगे

भोपाल (नप्र)। एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने दोनों की 5-5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आरोपी पक्ष के वकील ने भी रिमांड का विरोध नहीं किया।

सीबीआई ने कोर्ट में पेश पीआर आदेश में कहा कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक, दोनों के अलग-अलग बयानों में विरोधाभास सामने आया है। ऐसे में दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना जरूरी है। सीबीआई ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाने के लिए दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड आवश्यक है।

समर्थ सिंह पहले से 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर था। शुक्रवार को रिमांड खत्म होने के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। दोपहर 12:34 बजे से 2:08 बजे तक दोनों आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद रहे। इसके बाद सीबीआई टीम उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गई।

सूत्रों के मुताबिक, रिमांड के दौरान सीबीआई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी समर्थ से यह भी पूछेगी कि फरारी के दौरान वह कहां रहा और किन लोगों के संपर्क में था।

चेहरे पर बेचैनी, घूरती नजरें, कभी भोपाल कोर्ट में 'धमक' के साथ एंट्री लेने वाली गिरिबाला सिंह का ऐसा है हाल

पूर्ज जज गिरिबाला सिंह अपनी बहू ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई की रिमांड पर हैं। गिरिबाला सिंह की पेशी भोपाल कोर्ट में हुई, जहां कभी वह जज थीं। आज उसी कोर्ट में आरोपी के रूप में कटघरे में आई थीं। कटघरे में मॉ और बेटा डेढ घंटे से अधिक समय तक आरोपी के रूप में खडे रहे। उसकी बेचैनी चेहरे पर दिख रही थी। रिमांड मिलने

धमक के साथ होती थी एंट्री

गिरिबाला सिंह भोपाल कोर्ट में जज रही हैं। वह 15 जुलाई 2021 से 28 फरवरी 2023 तक यहां पदस्थ रही हैं। उस समय कोर्ट परिसर में गिरिबाला सिंह की एंट्री धमक के साथ होती थी। एंट्री के साथ कोर्टरूम में लोग खड़े हो जाते थे। आगे पीछे पूरा लाव लश्कर होता था। मगर आज उसी कोर्ट परिसर में सब कुछ बदला हुआ था। एक इशारे पर खड़े होने वाले लोग आज सामने खड़े होने को तैयार नहीं थे।

दो जून तक की है रिमांड

गिरिबाला सिंह दो जून तक दोपहर दो बजे तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। सीबीआई इन पांच दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन करेगी। 28 मई तक सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से सात घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद गिरफ्तार कर ले गई थी।

भोपाल कोर्ट से मिल गई थी जमानत

दरअसल, गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को हुई थी। 13 मई को परिजनों ने हंगामा किया था। साथ ही हत्या का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन गिरिबाला सिंह को भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।

भीषण गर्मी में भोपाल में बिजली-पानी संकट

करोंद में फूटी कोलार लाइन, मंत्री सारंग निरीक्षण करने पहुंचे, अफसरों को फटकार लगाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल में दिन में 43 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में कई इलाकों में बिजली और पानी का संकट है। रात में हर रोज 50 से ज्यादा इलाकों में बिजली गुल हो जाती है। वहीं, मेट्रो और 10 लेन अयोध्या बायपास के निर्माण पानी की लाइनें लगातार फूट रही है। शुक्रवार को भी करोंद में कोलार लाइन फूट गई। इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर अफसरों को फटकार लगाई।

लाइन फूटने की वजह से आज करोंद समेत करीब एक लाख आबादी को पानी नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार, करोंद चौराहे के पास गुरुवार सुबह मेट्रो की खुदाई के दौरान कोलार पाइप लाइन फूट गई। इसके कारण पुराने भोपाल के

बड़े हिस्से में पानी सप्लाई प्रभावित हो गई। शुक्रवार को करीब 1 लाख आबादी तक पानी नहीं पहुंचेगा। पिछले 15 दिन में मेट्रो और एनएचएआई की खुदाई के दौरान 14वीं बार पाइप लाइन टूटी है।

पानी नहीं मिलने से परेशान हो रहे लोगों की समस्या को देखते हुए मंत्री सारंग दोपहर 12 बजे करोंद इलाके में पहुंचे। इस दौरान एनएचएआई, जिला प्रशासन, नगर निगम, मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री सारंग ने बताया, 10 लेन अयोध्या बायपास प्रोजेक्ट चल रहा है। बीच-बीच में ठेकेदार की लापरवाही से पीने की पाइप लाइन फूट रही है। इसे लेकर लोग खासे परेशान हैं। इसके चलते आज अफसरों के साथ निरीक्षण किया।

मप्र से दिग्विजय सिंह की सीट पर कमलनाथ जाएंगे राज्यसभा या बाहरी को मिलेगा मौका?

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव हैं। कांग्रेस के खाते में एक सीट जा रही है। यह सीट दिग्विजय सिंह की है। दिग्विजय सिंह पहले ही राज्यसभा जाने से मना कर चुके हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ को राज्यसभा भेजा सकता है। बुधवार को नई दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

राज्यसभा की तीन सीटें हो रही हैं खाली- मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इनमें दो

सीटें बीजेपी की हैं। जनवरी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने घोषणा की थी कि वह मध्य प्रदेश से जून में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की एकमात्र सीट खाली कर देंगे।

उम्मीदवारों की है लंबी सूची- प्रदेश कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जून में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए एआईसीसी के पास उम्मीदवारों की एक लंबी सूची है। इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पूर्व राज्यसभा सांसद बी के हरिप्रसाद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सहित कई अन्य नाम शामिल हैं।

कांग्रेस की आएंगी पांच सीटें- वहीं, इस रेस में कमलनाथ का नाम शामिल होता है तो इससे चयन प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा की कुल 26 सीटें खाली होने के बावजूद कांग्रेस के हिस्से में केवल पांच सीटें ही आएंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट खाली हो रही है। ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण है।

- **दो विधायक हैं वोट से वंचित-** मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो गई है। विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा को वोटिंग का अधिकार नहीं है। तीसरी एमलए निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट में दल बदल का मामला लंबित है। ऐसे में हो सकता है कि वह भी वोट न दें। एमपी से राज्यसभा की एक सीट पर जीत के लिए 58 विधायकों की जरूरत है।
- **बीजेपी के पास हैं 165 विधायक-** वहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 165 विधायक हैं। ऐसे में दो सीटों पर उनकी जीत पक्की है। इसके बाद उनके पास 49 विधायक बचते हैं। राज्य बीजेपी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि अगर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी होती है तो बीजेपी तीसरी सीट पर चुनाव करवाने का मौका भुनाने से पीछे नहीं हटेगी।